www.navpradesh.com
दैनिक नवप्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...
अंदर के पृष्ठों पर ◆◆ 2 | छत्तीसगढ़ 4 | अभिव्यक्ति 9 | कारोबार/खेल
रायपुर, शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 कृष्ण पक्ष-नवमी, विक्रम संवत -2083 / वर्ष-15 अंक- 179 पृष्ठ-12 मूल्य-5 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

प्रदेश में खरीफ फसलों का होगा डिजिटल 'एक्स-रे', गड़बड़ी पर नपेंगे अफसर

■ शत-प्रतिशत व पारदर्शी गिरदावरी के कड़े निर्देश

■ राजस्व विभाग का फरमान, लापरवाही पर होगी सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान, मक्का और प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली व अरहर की खरीदी की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक बड़ा और कड़ा रुख अपनाया है। विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को खरीफ फसल की शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित गिरदावरी सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। शासन ने साफ कर दिया है कि गिरदावरी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हेरफेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गांव-गांव में होगी मुनादी, जन-प्रतिनिधियों के सामने खुलेगा रिकॉर्ड

गिरदावरी की तिथियों से ग्रामीणों को अवगत कराने के लिए गांवों में कोटवारों के जरिए मुनादी कराई जाएगी। गिरदावरी के दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी जांच के समय उपस्थित रहने का अवसर दिया जाएगा साथ ही किसान स्वयं उपस्थित होकर अपना फोटो खिंचवा सकते है।

20 सितम्बर तक गिरदावरी पूरी होगी

प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए शासन ने स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है। इसके तहत 20 सितंबर 2026 तक गिरदावरी का कार्य पूर्ण कर खसरा एवं भुईयां सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि व त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 25 सितंबर 2026 को ग्रामवार फसल क्षेत्राच्छादन प्रतिवेदन का प्रारंभिक प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर प्राप्त होने वाली दावा-आपत्तियों का निराकरण करते हुए 30 सितंबर 2026 तक खसरा पांचसाला और भुईयां सॉफ्टवेयर में अंतिम संशोधन कर दिया जाएगा।

7 स्तरीय भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

छत्तीसगढ़ में गिरदावरी प्रक्रिया की शुद्धता, पारदर्शिता और मैदानी फर्जीवाड़े पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए शासन ने उच्च अधिकारियों से लेकर मैदानी अमले तक 7-स्तरीय भौतिक सत्यापन की सख्त व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत पटवारी अपने हल्के के शत-प्रतिशत रकबे का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक और कृषि विस्तार अधिकारी 25-25 प्रतिशत रकबे की जांच करेंगे, जबकि तहसीलदार व नायब तहसीलदार को 10 प्रतिशत और अनुविभागीय अधिकारी को 5 प्रतिशत रकबे के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।प्रशासनिक कसावट को और मजबूत करते हुए जिला स्तरीय अधिकारी 1प्रतिशत तथा राज्य व संभाग स्तरीय अधिकारी 0.1 प्रतिशत गिरदावरी का औचक निरीक्षण करेंगे।

फसल बदली तो फोटो खींचना अनिवार्य, गलत एंट्री पर गिरेगी गाज

सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि यदि किसी किसान ने धान की जगह अन्य फसल बोई है या जमीन खाली छोड़ी है, तो पटवारी और राजस्व निरीक्षक को मोबाइल से उस खेत का खसरावार फोटो अपलोड करना होगा। राजस्व रिकॉर्ड और वास्तविक बोए गए रकबे में अंतर पाए जाने पर संबंधित मैदानी अमले और पर्यवेक्षण अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी।

आज बेबाक

सही बात है। हर नेता पीएम मोदी जैसा सहनशील नहीं होता। जो गंदी- गंदी गाली देने वालों को माफ कर दे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने अपनी महिला मित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उदयनिधि स्टालिन को पुलिस से घसीटवा कर उठवा लिया। आधा दर्जन धाराओं में अपराध दर्ज करा दिया। यह वही पेंगुइन है जो अपने बाप के मुख्यमंत्री रहते सनातन धर्म को बीमारी बताता था। उसने सोचा अब वो नेता प्रतिपक्ष है इसलिए जो मुंह में आए बक देगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन नये सीएम ने इस बीमारी का इलाज कर सारी हेकड़ी निकाल दी।

विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना का दावा गलत : नायडू

नई दिल्ली (वार्ता)। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना के दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा है कि ऐसी बातों से हवाई यात्रियों में अनावश्यक चिंता पैदा होती है। श्री नायडू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और गैर-जिम्मेदाराना है कि सरकार की विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी योजना का प्रस्ताव नहीं है। उल्लेखनीय है कि मीडिया में इस तरह की खबरें आयी थीं कि सरकार ने विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की अनुमति दे दी है।

गरमा-गरम

संबोधन: जेन-जी को मोहन भागवत का समर्थन, हर बात का तार्किक जवाब चाहते हैं युवा

'आंदोलन करना राष्ट्रविरोधी नहीं'

■ जेन-जी और जेन-अल्फा राष्ट्र की असली ताकत

नई दिल्ली/ए.। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 'इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' सम्मेलन के 15वें वर्षगांठ समारोह में शिरकत की। इस भव्य कार्यक्रम में देश-विदेश से आए करीब 2,000 छात्रों और युवाओं के बीच उन्होंने लोकतंत्र, विरोध प्रदर्शनों, शिक्षा के व्यवसायीकरण, रोजगार के नए विकल्पों और आज की युवा पीढ़ी की बदलती सोच जैसे बेहद गंभीर, प्रासंगिक और समकालीन मुद्दों पर खुलकर अपने विचार साझा किए।

देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों को लेकर युवाओं के मुखर होने और लगातार चल रही बहसों के बीच संघ प्रमुख का यह संबोधन बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज की युवा पीढ़ी-विशेषकर जेन-जी और जेन-अल्फा-पुरानी पीढ़ी से अधिक ईमानदार और ■ शेष पृष्ठ 8 पर

संवाद की कमी और आंदोलनों का जिक्र

देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए लंबे आंदोलनों का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने माना कि यह स्थिति सरकार और युवाओं के बीच संवादहीनता या बातचीत की कमी के कारण उत्पन्न हुई। यदि समय रहते नीति निर्माताओं और युवाओं के बीच पारदर्शी संवाद स्थापित हो जाता, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती।

युवाओं की तार्किक सोच और सवाल पूछने की प्रवृत्ति

पहले के समय में बड़े-बुजुर्गों की बात बिना किसी सवाल के मान ली जाती थी, लेकिन आज का युवा हर विषय पर तार्किक, वैज्ञानिक और तथ्य आधारित जवाब चाहता है। इस प्रवृत्ति को दबाने या चुप कराने के बजाय बुजुर्गों और समाज को उनकी बातों को गंभीरता से सुनना और समझना चाहिए।

जेन-जी की देशभक्ति और ईमानदारी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत के अनुसार, आज की युवा पीढ़ी (विशेषकर जेन-जी और जेन-अल्फा) को लेकर जो आम धारणाएं हैं, वास्तविकता उससे अलग है। यह युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार, देशभक्त और देश के प्रति जवाबदेह है। इनकी सोच को नकारात्मक मानने के बजाय इनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता है।

रोजगार और उद्यमिता पर जोर

आजीविका के लिए केवल सरकारी या प्राइवेट नौकरियों पर निर्भर रहने की मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। युवाओं को स्वरोजगार अपनाने और नए व्यावसायिक अवसर (स्टार्टअप्स) सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे वे न केवल खुद आत्मनिर्भर बनें बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकें।

आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार

युवाओं द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करना किसी भी स्थिति में राष्ट्रविरोधी नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपनी बात को मुखरता से रखना और संवाद शुरू करना नागरिकों का वैध अधिकार है, बशर्ते यह प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक मार्ग पर चले।

शिक्षा का व्यवसायीकरण और उसकी सुलभता

शिक्षा प्रणाली पर गहरी चिंता जताते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा कोई कमर्शियल बिजनेस या मुनाफा कमाने का साधन नहीं है। देश के हर वर्ग, हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसानी से पहुंचे, इसके लिए सरकार के साथ-साथ पूरे समाज और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर ठोस बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा।

पाकिस्तान और चीन के साथ कूटनीतिक रुख

देश की सुरक्षा और विदेश नीति पर बात करते हुए यह कहा गया कि जब भी राष्ट्र पर संकट या युद्ध की स्थिति हो, तब पूरे देश को एकजुट होकर सरकार का साथ देना चाहिए। हालांकि, युद्ध या तनाव की स्थिति हमेशा स्थायी नहीं होती, इसलिए संघर्ष समाप्त होने के बाद कूटनीतिक बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रखे जाने चाहिए।

महिलाओं का नेतृत्व और समान अधिकार

भारतीय समाज और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए यह समर्थन किया गया कि देश और समाज के विकास के लिए महिलाओं का नेतृत्व में आगे आना अनिवार्य है। उन्हें हर क्षेत्र में बराबरी का हक और समान अधिकार मिलने ही चाहिए।

पीएम और गृहमंत्री सदन में बयान दें: नेता प्रतिपक्ष खरगे

नई दिल्ली/वार्ता। संसद में गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने की विपक्ष की मांग लगातार जारी है। गुरुवार को राज्यसभा में सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को निर्देश दिया कि वे विपक्ष की भावना गृह मंत्री तक पहुंचाएं। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देने का अनुरोध किया, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

नेता प्रतिपक्ष खरगे की मांग: नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में कहा कि विपक्ष देश के 140 करोड़ लोगों के मुद्दे उठा रहा है और सरकार चर्चा से भाग रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग की।

संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की आपत्ति: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खरगे के अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन को अपने हिसाब से नहीं ■ शेष पृष्ठ 8 पर

रिजिजू की राहुल गांधी से मुलाकात, राजनीतिक मतभेद हैं, पर देशहित में संसद चलना जरूरी

संसद के मानसून सत्र में लगातार जारी हंगामे और गतिरोध के बीच, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को 'सकारात्मक' बताते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के साथ निरंतर संवाद और बेहतर समन्वय चाहती है। रिजिजू ने बताया कि राहुल गांधी के साथ एक विशेष मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक विरोध का मतलब दुश्मनी नहीं होता। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए।

विधेयक पारित: पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 'कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026' को ध्वनिमत से पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की। सदस्यों द्वारा लगातार हंगामा जारी रखने के कारण पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे और बाद में हालात न सुधरने पर शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

तरुण तेजपाल को 2013 रेप केस में 10 साल की सजा

नई दिल्ली/वार्ता। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को सीनियर पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 के चर्चित रेप केस में 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मापुसा सेशन कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें मई 2021 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

यह है पूरा मामला नवंबर 2013 में 'तहलका' मैग्जीन के तत्कालीन एडिटर-इन-चीफ़ तरुण तेजपाल पर गोवा के एक होटल में उनकी जूनियर सहयोगी ने यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था। घटना के बाद तेजपाल ने ईमेल भेजकर पीड़िता से बिना शर्त माफी भी मांगी थी।

हाईकोर्ट ने गोवा सरकार की अपील मंजूर करते हुए आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(के) के तहत 10-10 साल की कठोर कैद और 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 354ए, 354बी, 341 और 342 के तहत भी सजा और जुर्माना तय किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि तेजपाल की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

वेनेजुएला समेत अमेरिका का दुनिया के 60 फीसदी तेल पर नियंत्रणः ट्रंप

वाशिंगटन (स्पुतनिक/वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का दुनिया के 60 प्रतिशत तेल पर कंट्रोल है, जिसमें वेनेजुएला के रिसोर्स को भी अमेरिकी क्षमता का हिस्सा माना गया है। लास वेगास में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा, हमारे पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज़्यादा तेल और गैस है। अब इसमें वेनेजुएला को भी जोड़ लें। इसे जोड़ने पर, वेनेजुएला सहित हमारे पास दुनिया का 60 प्रतिशत तेल और गैस है। अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि

उन पर नार्को-टेररिज्म (नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा आतंकवाद) में शामिल होने के आरोपों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। मादुरो और फ्लोरेस ने न्यूयॉर्क की अदालत में आरोपों से इनकार किया।

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति रोड्रिग्ज को सौंप दिया। ■ शेष पृष्ठ 8 पर

23,731 करोड़ की 'गोबरधन'योजना को मंजूरी

■ केन्द्रीय कैबिनेट : देश में संपीड़ित बायोगैस क्षेत्र को बढ़ावा देने बनी योजना

नई दिल्ली/ए.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना 'गोबरधन' को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवशेष, गोबर, शहरी जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधनों को संपीड़ित बायोगैस, जैविक खाद और ग्रामीण आय के स्रोत में बदलना है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी और भारत की ऊर्जा व्यवस्था में संपीड़ित बायोगैस को एक प्रमुख ■ शेष पृष्ठ 8 पर

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार, यह योजना किसानों, सहकारी समितियों, फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगी। साथ ही कृषि अवशेष, गोबर और शहरी जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जैविक खाद के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि गोबरधन योजना ऊर्जा सुरक्षा, 'वेस्ट टू वेल्थ', आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

सुशासन की नई व्यवस्था : पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा

सीमांकन मामलों में लापरवाही पर सीएम सख्त, समय-सीमा में करें निराकरण

■ जनहित की योजनाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, मुख्यमंत्री साय ने दिए स्पष्ट निर्देश

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में 'पारस पोर्टल' की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित की योजनाओं और आम नागरिकों के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों की राज्यस्तरीय समीक्षा की जाएगी।

सीमांकन मामलों में नाराजगी और निर्देश: मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में सीमांकन से जुड़े लंबित ■ शेष पृष्ठ 8 पर

एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन

मुख्यमंत्री ने किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टैक के तहत प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही के कारण यदि कोई किसान वंचित रहा, तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी।

■ अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से होगी राज्यस्तरीय समीक्षा

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन (1076) पर अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनमें से 65 हजार से ज्यादा का निराकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, पंचायत और राजस्व विभागों से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।

स्कूलों में किचन गार्डन और पौधारोपण

मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को ताजा और पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए स्कूल परिसरों में 'किचन गार्डन' विकसित करने तथा सहजन व कटहल जैसे उपयोगी पौधे लगाने के अभियान को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

6 नए जिलों में खेल अधिकारियों के पदों को मंजूरी

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य शासन ने खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 6 नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती में खेल अधिकारी के नए पदों को मंजूरी दी है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मंत्रालय से विगत 4 अगस्त को इन पदों की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अतीक के बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

■ झांसी जेल जा रहे थे भाई से मिलने

प्रयागराज/ए.। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान (21) की एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे झांसी से 70 किलोमीटर पहले पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ। अबान अपनी क्रेटा कार में चार दोस्तों के साथ प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था। तेज रफ्तार क्रेटा कार हाईवे पर अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह हवा में

उछल गई और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के वक्त कार ■ शेष पृष्ठ 8 पर

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार

डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं त्वरित, पारदर्शी और आसान

प्रमुख सेवाएं

- ✓ जाति प्रमाण पत्र
- ✓ आय प्रमाण पत्र
- ✓ निवास प्रमाण पत्र
- ✓ विवाह प्रमाण पत्र
- ✓ राशन कार्ड सेवाएं
- ✓ पेंशन योजनाएं
- ✓ नाम परिवर्तन सेवा
- ✓ व्यापार लाइसेंस

आपकी ज़रूरत की सेवाएं, अब घर बैठे एक क्लिक में

639 सेवाएँ

36 विभाग एक मंच पर

17,065 सेवा केंद्र

45 लाख+ आवेदन

S- 48665

अधिक जानकारी हेतु स्कैन करें

जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार
sewasetu.cgstate.gov.in

92034 06400

सूबेदार/एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम में नामों पर सियासत गरमाई, पीएससी ने सही बताया

■ न्यूज, स्पेसरानी जैसे नामों को लेकर कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया

■ भाजपा ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग उठाई

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ पीएससी आयोजित सूबेदार/उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर परीक्षा 2024 की प्रारंभिक लिखित परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों के नामों को लेकर सोशल मीडिया में खबरें चलीं और विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया तो सियासत गरमा गई । पीएससी ने भी इस पर स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि जारी परीक्षा परिणाम में प्रदर्शित अभ्यर्थियों के नाम वही हैं जो संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कर अंतिम रुप से सबमिट किए गए हैं । भाजपा ने भी कांग्रेस के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस को युवाओं से माफी मांगने की मांग कर दी है ।

गुरुवार को कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने लिखित परीक्षा परिणाम की सूची जारी कर न्यूज, स्पेसरानी, तूफान जैसे नामों को लेकर कहा कि सूची में शामिल नाम यह बताते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग और भाजपा सरकार परीक्षा को कितनी ज्यादा लापरवाह है। यह युवाओं के

भविष्य के साथ खिलवाड़ है । सोशल मीडिया में खबर वायरल होते ही शाम को लोक सेवा आयोग के अवर सचिव ने एक खंडन जारी किया जिसमें न्यूज, स्पेसरानी, ही, राम, भक्त प्रहलाद, टूफैल आदि नामों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इन नामों को लेकर भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारी प्रसारित की जा रही है । अभ्यर्थियों के वास्तविक नामों का उपहास करते हुए आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम को प्रश्नगत किया जा रहा है ।

पीएससी ने कहा है कि सभी अभ्यर्थी उक्त नामों से ही प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे । उनके प्रवेश पत्र में भी उनके नाम यथावत प्रदर्शित किए गए हैं । आयोग समस्त अभ्यर्थियों को सलाह देता है कि वे ऐसी भ्रामक तथा असत्य जानकारी पर विश्वास न करें । वे केवल पीएससी की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर विश्वास करें ।

पीएससी की भर्ती परीक्षाएं संदेह के घेरे में

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने अपने बयान में कहा कि सरकार युवाओं का भरोसा पूरी तरह से खो चुकी है। एडीईओ भर्ती, वनरक्षक, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, आरआई प्रमोशन परीक्षा सहित विगत ढाई सालों के दौरान जितने भी प्रमोशन और भर्ती परीक्षा हुए है वे सभी संदेह के घेरे में है। आरआई प्रमोशन परीक्षा में परिजन एक साथ बैठकर पेपर लिखते पाए गए, पीएससी परीक्षा के पेपर अपात्र एलबी से जंचवाए,

उनके नाम सार्वजनिक किए, वनरक्षक परीक्षा में हैदराबाद की इवेंट कंपनी को शामिल कर फर्जीवाड़ा किया गया। राजनांदगांव आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में तो पूरी गड़बड़ी का ठीकरा एक आरक्षक पर फोड़कर लीपापोती कर दी गयी, जिसके चलते आरक्षक अनिल रत्नाकर को जान गवानी पड़ी। हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में बड़े अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे लेकिन कार्यवाही के नाम पर केवल लीपापोती की गई। समग्र शिक्षा में 1400 पदों पर भर्ती हुई 17 तारीख की रात को अभ्यर्थियों को सूचना भेजी गई, 18 तारीख को परीक्षा लिए और उसी दिन इंटरव्यू भी हो गया और 20 जुलाई को 1300 लोगों की लिस्ट जारी भी कर दी गई। बेहद स्पष्ट है कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची लेनदेन करके पहले से ही तैयार कर लिया गया था।

पीएससी ने कांग्रेस के दुष्प्रचार की खोली पोल: भाजपा

इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उज्वल दीपक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा सूबेदार / उप निरीक्षक संवर्ग / प्लाटून कमांडर परीक्षा – 2024 के प्रारंभिक लिखित परिणाम को लेकर जारी आधिकारिक स्पष्टीकरण ने पूरे विवाद को समाप्त कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन नामों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा था, वे संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए

गए वास्तविक नाम हैं तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया उन्हीं नामों के आधार पर संचालित हुई है। आयोग ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक दावों का आधिकारिक रूप से खण्डन किया है। श्री दीपक ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर जब परिणाम में कुछ असामान्य नाम सामने आए, तब सामान्य अभ्यर्थियों की तरह उन्हें भी संदेह हुआ। इसलिए उन्होंने स्वयं सीजीपीएससी को टैग करते हुए आयोग से आग्रह किया कि यदि यह तकनीकी या टंकण सम्बन्धी विषय है तो तत्काल सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी किया जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं के मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस विषय पर राजनीतिक लाभ लेने के बजाय संस्थागत स्पष्टता की मांग की थी। आयोग ने अब अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी तथ्यों को सार्वजनिक कर दिया है।

न्यूज गैलरी

तकनीकी खराबी के कारण उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट ठप, सुधार जारी

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्वर संबंधी तकनीकी समस्या के कारण उपयोगकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट वर्तमान में अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। मिली जानकारी के अनुसार, यह समस्या वेबसाइट के एसएसएल(सिक्योर सॉकेट्स लेयर) सर्टिफिकेट से जुड़ी तकनीकी त्रुटि के कारण उत्पन्न हुई है। इस सिक्योरिटी एरर की वजह से छात्र और अन्य उपयोगकर्ता पोर्टल का सुरक्षित रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने इसका तत्काल संज्ञान लिया है और सुधार कार्य शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की तकनीकी टीम एसएसएल सर्टिफिकेट के नवीनीकरण और सिस्टम री-कॉन्फ़िगरेशन के काम में लगी हुई है।उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खामी को जल्द से जल्द दूर करने के प्रयास जारी हैं। जैसे ही मेंटेनेंस का काम पूरा होगा, वेबसाइट की सभी ऑनलाइन सेवाएं और सुविधाएं पूर्ववत चालू कर दी जाएंगी।

'ऑपरेशन निश्चय' के तहत 120 पौवा अवैध शराब और बाइक के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायपुर/नवप्रदेश। थाना खरोरा पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 120 पौवा (कुल 21 लीटर 600 मिलीलीटर) देशी मसाला शराब और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 72,000 रुपये है। थाना प्रभारी खरोरा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम नहरडीह में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की और आरोपी आत्माराम घृतलहरे (52 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 08 पचरी, थाना खरोरा) को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से तीन प्लास्टिक बोरियों में भरा 'सवा शेरा' कंपनी का 120 पौवा सीलबंद मसाला शराब बरामद हुआ। शराब परिवहन से जुड़े वैध कागजात पेश न करने पर पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन में की गई है।

जिले के 262 विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण हेतु 16.90 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर/नवप्रदेश। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूली बालिकाओं को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिन विद्यालयों में बालिका शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां मॉडल बालिका शौचालय निर्माण के लिए प्रोजेक्ट गरिमा के तहत वीबी जीरामजी, गौण खनिज एवं डीएमएफ के सहयोग से 262 विद्यालयों में कार्य स्वीकृत किए गए हैं। बालिका शौचालयों के निर्माण के लिए 5 लाख एवं 7 लाख रुपये लागत के दो मॉडल तैयार किए गए हैं। इन शौचालयों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत व्यवस्था, कन्सील्ड फ्लश सिस्टम, उच्च गुणवत्ता के सेनेटरी उपकरण, पर्याप्त जलापूर्ति के लिए प्रेशर बूस्टर तथा दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले के 262 विद्यालयों में निर्माण कार्यों के लिए कुल 1690.82 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें वीबी जीरामजी के अंतर्गत 1308.82 लाख रुपये, गौण खनिज मद से 30 लाख रुपये तथा डीएमएफ मद से 352 लाख रुपये शामिल हैं। निर्माण कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायतों को बनाया गया है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालन अभियंता, ऋश्वस् द्वारा मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है एवं समस्त विख. के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद के तकनीकी अमलों को निर्माण मानकों के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रत्येक विकासखंड में तकनीकी अमले की उपस्थिति में लेआउट तैयार कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है।

लंबित प्रकरणों में स्पष्ट कारण दर्ज करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

रायपुर/नवप्रदेश। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं बैंकिंग सेवाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने पाया कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के लंबित एवं अस्वीकृत प्रकरणों में कई मामलों में स्पष्ट एवं उचित कारण अंकित नहीं किए गए हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक लंबित एवं अस्वीकृत प्रकरण में नियमानुसार स्पष्ट एवं तथ्यात्मक कारण दर्ज किए जाएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं बैंकर्स को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए योजनाओं के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग एवं बैंक नियमित समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें।

15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान, हर गांव में मुक्तिधाम और बालिकाओं के लिए स्कूलों में शौचालय

मुख्यमंत्री ने 'मेरी बेटी-मेरा अभिमान' अभियान का मंत्रालय में किया शुभारंभ

■ वीबी-जी राम जी मिशन से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति, 6,855 करोड़ रुपए से रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का होगा विस्तार

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारतङ्करोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी 'मेरी बेटीङ्कमेरा अभिमान' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे, जिनकी प्रति इकाई लागत 6 लाख रुपए होगी। इसके अतिरिक्त 18.22 करोड़ रुपए की लागत से 549 मुक्तिधामों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी प्रति इकाई लागत 3.32 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद अथवा डिफंक्ट बोरवेलों में 52.14 करोड़ रुपए की लागत से सैंड फिल्टर एवं रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। प्रति इकाई लागत लगभग 52 हजार रुपए निर्धारित की गई है। इससे भू-जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल स्वीकृत कर शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

318 प्रकार के विकास कार्यों से बदलेगी गांवों की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य तथा 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती

मुख्यमंत्री ने बताया कि आजीविका संवर्धन के अंतर्गत ग्रामीण हाट-बाजार, कृषि उपज भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन तथा पशुपालन से संबंधित अधोसंरचना विकसित की जाएगी। वहीं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़ एवं चक्रवात आश्रय, ड्रेनेज, तटबंध, जंगलों में आग की रोकथाम तथा प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण विकास और रोजगार का सबसे बड़ा अभियान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा तथा मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारतङ्क2047' के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। भारत सरकार से योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

20 स्कूलों में 2 सौ निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

■ निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों को मंडल की बैठक में मिली स्वीकृति

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिको की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सुधार हो रहा है। विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें की शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले।

प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक को सम्बोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किये। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार

कल्याण मंडल की पंचम कार्यकाल की नवम बैठक आज गुरूवार को नवा रायपुर स्थित मण्डल कार्यालय में श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन लखन लाल देवांगन, मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, उप सचिव श्रम विभाग विपुल गुप्ता, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े, कल्याण प्रशासक सुनील मिश्रा, मण्डल के सचिव गिरीश रामटेके सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के 20 चयनित विद्यालयों में 200 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6वीं में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

फैक्ट्री में काम के लिए ले जाए जा रहे 16 बच्चों का रेस्क्यू, नियोक्ता गिरफ्तार

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के त्वरित हस्तक्षेप के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की संयुक्त टीम ने महज डेढ़ घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए बच्चों को बस से बरामद किया। मामले में एक नियोक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बच्चों को ले जाने वाले पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा को 5 अगस्त की शाम एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की ओर से सूचना मिली थी कि रायपुर से कुछ बच्चों को बस के जरिए बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा है।सूचना मिलते ही आयोग ने मामले को

गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद संयुक्त टीम ने अभियान शुरू किया और करीब डेढ़ घंटे के भीतर बस को रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

बस में मिले 16 बच्चे, 7 बच्चे 14 से 16 उम्र के: रेस्क्यू की गई टीम को बस में कुल 16 बच्चे मिले। इनमें 7 बच्चे 14 से 16 वर्ष आयु वर्ग के नाबालिग हैं। सभी बच्चे बैगा जनजाति से संबंधित बताए जा रहे हैं और राजनांदगांव तथा कबीरधाम जिले के रहने वाले हैं।रेस्क्यू के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाल आश्रय गृह में रखा गया है। यहां बच्चों की काउंसलिंग के साथ-साथ उनकी देखभाल की जा रही है

मशरूम फैक्ट्री में काम कराने के लिए ले जाने का आरोप: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चों को कचन्दूर स्थित मॉडर्न एग्रो मशरूम में काम कराने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस मामले में नियोक्ता लक्ष्मण पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय में वृद्धि और हरित अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल

सीबीजी इकोसिस्टम विकास के लिए केन्द्र ने मंजूर किए 50 करोड़

■ सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि, राशि प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम के विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी प्रयासों की सराहना करते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना 2026-27 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान

बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

जैव अवशेषों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा: मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति राज्य के कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। इससे कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा, किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा तथा पराली और अन्य जैव अवशेषों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को जैव ईंधन एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। सीबीजी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसानों की आय, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जून 2026 को अधिसूचित किया है।

सुविचार

प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है लेकिन प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है।

पीडीए की नई परिभाषा

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ माह ही शेष रह गये हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों अखिलेश यादव जहां संसद में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और इसे लेकर संसद के बाहर लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं जिसे अब कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन में शामिल अन्य दलों का भी समर्थन मिल रहा है यहां तक की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर आक्रामक रूख अपनाये हुए थे वे भी समाजवादी पार्टी के सूर में सूर मिलाते हुए संसद के बाहर चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साधू के वेश में चंदा चोरी का नाटक करके साधु संतो की नाराजगी मोल ले ली थी। जिन्होंने पप्पू यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा था। जब यह बात अखिलेश यादव के समझ में आई तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए ब्राम्हण जाति को साधने के लिए अपने पीडीए की परिभाषा फिर एक बार बदल ली पहले वे पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते थे बाद में उन्होंने ए का मतलब अल्पसंख्यक की जगह अगड़ा बताना शुरू कर दिया था और अब उन्होंने पीडीए में पी का मतलब पंडित बताया है। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राम्हण समाज के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि पीडीए ही ब्राम्हणों के हितों की रक्षा करेगा। दरअसल अखिलेश यादव अपना जनाधार उत्तरप्रदेश में कमजोर पड़ता जा रहा है। वहां का पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ रहा है सिर्फ यादव समाज ही समाजवादी पार्टी का समर्थक है लेकिन इसमें भी भाजपा सेंध लगा रही है। दलित वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी से छिटकने का खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायावती इस बार उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव पुरी ताकत से लड़ने जा रही हैं। यह चुनाव मायावती के लिए करो या मरो वाला है। मायावती जानती है कि यदि इस बार भ उनकी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। आज भी उनके साथ दलित समाज का एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। जाहिर है मायावती समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगी वे न सिर्फ दलित वोट को बल्कि मुस्लिम वोट को भी समाजवादी पार्टी के पाले से अपनी ओर खींच सकती हैं। समाजवादी पार्टी के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में भी इस बार अस्सद्दुदीन ओवैसी सेंध लगाने जा रहे हैं। उन्होंने पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की अपील की थी लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण अखिलेश यादव ओवैसी के साथ हाथ मिलाने में हिचक रहे हैं। अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाएंगे। भले ही वे पिछले विधानसभा चुनाव की तरह एक भी सीट न जीत पाये लेकिन कई सीटों पर चुनावी गण्ति को गड़बड़ा देंगे। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव ने पीडीए की नई परिभाषा गढ़ी है। और पी का मंतलब पंडित बताकर ब्राम्हणों सहित अन्य अगड़ी जातियों को अपने पालें में लाने की कवायद कर रहे हैं। बिहार विधानसभा की बाकींपुर सीट पर हुए उपचुनाव में इस तरह से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने अगड़ा बाहुल पीठ पर भाजपा को पराजित किया है। उससे भी अखिलेश यादव उत्साहित हो गये हैं। उन्हें लग रहा है कि अब अगड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा से नाराज हो गया है। ऐसे में स्वर्ण वोटों को साधने का उन्हें अनुकूल अवसर नजर आ रहा है। इसमें उन्हें इतनी सफलता मिलती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

आतंकी माड्यूल का खुलासा ; सतर्कता जरूरी

पंजाब पुलिस ने एक आतंकी माड्यूल का खुलासा करते हुए चार नाबालिग सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से अवैध हथियार भी जब्त हुए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान वहां बम फेकने की योजना बनाई गई थी। आतंकी माड्यूल के इस खुलासे के बाद संसनीय फैल गई है। एक बड़ा आतंकी हमला होने से बच गया है। यदि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और लंबा चलता तो वहां आंतकी वारदात हो जाती। पंजाब पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पुछताछ में उनसे कई चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। यह ठीक है कि फिल्हाल तो खतरा टल गया है लेकिन देश को बहलाने की साजिश आगे भी हो सकती है। इसलिए अतिरिक्त सर्तकता बरतना निहायत जरूरी है। पंजाब की तरह ही बंगाल में भी आतंकी माड्यूल का खुलासा हुआ है। जाहिर है पड़ौसी देश पाकिस्तान भारत में इसी आंतकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए वह भारत में ही रहने वाले गद्दारों को मोहरा बना रहा है और इनमें भी वह नाबालिग बच्चों का सहारा ले रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर, बंगाल और नई दिल्ली सहित देश के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम करना आवश्यक है और संदिग्धों के खिलाफ युद्धस्तर पर अभियान भी चलाना होगा। तभी पाक के नापाक मंसूबे नाकाम होंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो खतरा पैदा हुआ है वह दूर होगा।

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1880 - उचित वक्ता पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। 1996 - अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 13 हज़ार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्का पिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता चला। 1998 - केन्या एवं तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु। 1999 - पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ ने एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की। 2000 - रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन द्वारा एक क़ानून पर हस्ताक्षर कर अपनी शक्ति का विस्तार। 2003 - बगदाद में जार्डन दूतावास के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 12 लोगों की मृत्यु। 2005 - इस्रायल के वित्तमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। 2008 - सार्वजनिक क्षेत्र के देना बैंक ने अपनी प्रधान ब्याज दरें 0.75% बढ़ाकर 14.25% करने की घोषणा की।

गरीब किसानों के मसीहा डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन

डॉ देवेन्द्र नाथ शर्मा
शिक्षाविद

हरित क्रांति से एवरग्रीन रिवोल्यूशन तक

सरकार का उच्चतम नेतृत्व यदि किसी वैज्ञानिक को शोध एवं अनुसंधान की पूरी स्वतंत्रता दे, देश की समस्याओं के समाधान के लिए उसके संकल्प पर विश्वास करे और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, तो वह वैज्ञानिक अपनी पूरी ऊर्जा राष्ट्र के उत्थान में समर्पित कर सकता है। इस सत्य को साकार किया 1960 के दशक में किसानों के मसीहा बने कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति के माध्यम से उन्होंने भारत को भुखमरी से बचाया और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। देश उनका सदैव ऋणी रहेगा।

खाद्य संकट की घड़ी

1960 के दशक में बढ़ती जनसंख्या, सूखा और अकाल ने भारत की खाद्यान्न स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया था। 1965-66 के भीषण सूखे ने संकट को और गहरा कर दिया। पारंपरिक खेती पुराने बीजों, वर्षा पर निर्भरता और सीमित सिंचाई पर आधारित थी, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम रहता था। 1970 के दशक के आरंभ तक भारत अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए विदेश से आयातित अनाज पर निर्भर था। अमेरिका से पीएल-480 योजना के तहत गेहूँ मँगाना पड़ता था। उस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता थी—खाद्यान्न उत्पादन को कई गुना बढ़ाना। यदि ऐसा न होता, तो भूख और खाद्य असुरक्षा गंभीर संकट बन सकती थी।

हरित क्रांति की नींव

इसी चुनौतीपूर्ण काल में डॉ. मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से भारत के वातावरण के अनुकूल उच्च उपज वाली गेहूँ की किस्में विकसित करने का कार्य शुरू किया। बोरलॉग से मैक्सिकन अर्ध-बौनी किस्में प्राप्त की गईं और भारत में उनकी व्यवहार्यता का परीक्षण किया गया। ये किस्में उच्च उपज देने वाली होने के साथ-साथ रोग-प्रतिरोधी भी साबित हुईं। स्वामीनाथन ने विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों को इन किस्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इन राज्यों में गेहूँ की खेती के लिए अनुकूल जलवायु थी।

1966 में उन्होंने भारतीय सरकार को मैक्सिको से 18,000 टन उच्च उपज वाले बीज खरीदने के लिए राजी किया। इन बीजों के आने के साथ ही भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। परिणाम चमत्कारी

रहे। मैक्सिकन गेहूँ की किस्में अपनाने वाले किसानों की पैदावार और मुनाफा तेजी से बढ़ा। भारत का गेहूँ उत्पादन 1964 में लगभग 12 मिलियन टन से बढ़कर 1970 में लगभग 20 मिलियन टन हो गया। इसके बाद सरकार ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर घोषित कर दिया। आधुनिक कृषि पद्धतियाँ—उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, उन्नत सिंचाई तकनीकें तथा मशीनीकरण—इसके बाद देश के अधिकांश राज्यों में तेजी से अपनाई जाने लगीं। गेहूँ उत्पादन में सफलता ने चावल की खेती में भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामीनाथन ने चावल की कई उन्नत किस्में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे चावल उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारकर आत्मनिर्भर बनाया और खाद्य सुरक्षा को मजबूत नींव प्रदान की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य भंडारण व्यवस्था सुदृढ़ हुई। आज भारत विश्व के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल है।

एवरग्रीन रिवोल्यूशन

हरित क्रांति ने क्रांतिकारी बदलाव लाया, किंतु कई चुनौतियाँ भी खड़ी कीं। इसका लाभ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित क्षेत्रों तक सीमित रहा। छोटे और सीमांत किसानों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिला। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हुई, भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ, जैव विविधता घटी और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। कृषि लागत भी बढ़ गई। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वामीनाथन ने 'एवरग्रीन रिवोल्यूशन' (सदाबहार क्रांति) का विचार प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत कम पानी में अधिक उत्पादन, जैविक एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि तथा छोटे किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उद्देश्य था—प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

जीवन परिचय

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने कम फसल उत्पादन के कारण कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की गरीबी को प्रत्यक्ष देखा। परिवार उन्हें सर्जन बनाना चाहता था, किंतु 1943 के बंगाल अकाल (जिसमें लाखों लोग मारे गए) ने उन्हें भारत के खाद्य संकट से निपटने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप उन्होंने कृषि विज्ञान में करियर चुना।

1944 से 1954 तक के शैक्षणिक सफर में उन्होंने आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में डॉक्टरेट तथा पोस्ट-डॉक्टरेट सहित कई डिग्रियाँ प्राप्त कीं। 1949 में यूनेस्को ने आलू की फसल को पाले और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के शोध के लिए उन्हें फैलोशिप दी। 1954 में उन्होंने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) में कार्य आरंभ किया, जहाँ उनका अधिकांश शोध उर्वरकों और उन्नत किस्मों के माध्यम से चावल तथा गेहूँ के उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रहा।

1950 के दशक में मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग की सफलता के बारे में जानकर वे प्रेरित हुए। बोरलॉग द्वारा विकसित अर्ध-बौनी गेहूँ की किस्मों ने मेक्सिको को आयात-निर्भर देश से आत्मनिर्भर गेहूँ उत्पादक में बदल दिया था। इसी सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी।

पद और जिम्मेदारियां

स्वामीनाथन 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक, 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक तथा 1982 से 1988 तक फिलीपींस के लॉस बान्योस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक रहे। वे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष तथा 1989 से 1996 तक विश्व वन्यजीव कोष (भारत) के अध्यक्ष भी रहे। 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष और 2007 से 2013 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 1988 में उन्होंने एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जो स्वयं को गरीब-समर्थक, महिला-समर्थक और प्रकृति-समर्थक संगठन के रूप में परिभाषित करता है तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

सम्मान

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को उनके अमूल्य योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें 1967 में पद्म श्री, 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण से विभूषित किया। 1971 में फिलीपींस की रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया।

भाजपा: गलत निर्णयों की भरमार का दुष्परिणाम

राजीव खंडेलवाल

बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर हुई रणनीतिक भूल की तरह दतिया में भी भाजपा ने पिछले चुनाव के स्थापित, चिर-परिचित उम्मीदवार को बदलकर मानो "अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।"इसी एक निर्णय ने "हार की नींव" उसी दिन रख दी थी।

मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल रहे भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता एवं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो पिछले चुनाव में मात्र लगभग 7 हजार मतों से पराजित हुए थे, का टिकट काटने का तो कोई ठोस, उचित और विश्वसनीय कारण कार्यकर्ताओं न तो बताया गया, और न ही उन्हें ÷मनाने÷ का गंभीर प्रयास हुआ। उनका दिल्ली दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात न हो पाना भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा।

स्थिति तब और बिगड़ गई, जब टिकट कटने के विरोध में जिला संगठन के अधिकांश पदाधिकारियों ने "सामूहिक इस्तीफे" दे दिए। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने 'असंतुष्ट' नरोत्तम मिश्रा को संगठन अथवा सरकार में कोई सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर "संतुष्ट" कर नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की। परिणामतः "बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होय।"

नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना: हार का सबसे बड़ा कारण?

मीडिया में सूत्रों के हवाले से यही कारण आया कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जिन आशुतोष तिवारी को उनका स्थान दिया गया, क्या उनका भी उतना ही व्यापक सर्वे कराया गया था?

राजनीति में जब किसी स्थापित नेता का टिकट काटना होता है, तो सबसे आसान तर्क "तथाकथित सर्वे" ही बन जाता है। पर यदि सर्वे ही "ब्रह्मवाक्य" होता अंतिम सत्य हो तो अनेक चुनावी परिणाम उसके विपरीत क्यों आते?

वस्तुतः नरोत्तम मिश्रा के लिए "कुआं-खाई" जैसी स्थिति थी, तो भाजपा नेतृत्व "ऊहापोह" में फंसा था। शायद इसीलिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा उम्मीदवार की घोषणा हुई। "आखिरी समय में आनन-फानन" का फैसला अक्सर "गले की हड्डी" बन जाता है।

कांग्रेस की अधिकांश मोर्चों पर भाजपा पर बढ़त

अपेक्षाकृत ज्यादा गुटबाजी से ग्रस्त कांग्रेस ने यहां 2 दिन पहले ही उम्मीदवार घोषित कर भाजपा से "बाजी मार ली"। लंबे समय बाद ऐसा चुनाव देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस अपेक्षाकृत "व्यवस्थित" दिखी और भाजपा "अव्यवस्थित" हो गई।

यद्यपि संसाधनों और बूथ प्रबंधन में भाजपा की दक्षता निर्विवाद है, लेकिन इस चुनाव में "जन ने "तंत्र" पर भारी पड़ने" का संदेश दे दिया।

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही भाजपा में भीतरघात की चर्चा "आम" हो गई थी। इससे निपटने की जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व की थी, जिस पहली परीक्षा में ही वे असफल (फेल) हो गये। परिणाम आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का कथन कि "यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी" - इसका सीधा मतलब पार्टी अभी तक दोषी ही तय नहीं कर पाई।

4 अगस्त को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जांच के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई। आश्चर्यजनक रूप से समिति ने मात्र 6-7 घंटों में, दतिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए बिना ही पूरे जिला संगठन को भंग करने की अनुशंसा कर दी। प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। सवाल उठता स्वभाविक है कि क्या यह समस्या के समाधान का प्रयास था या सिर्फ "बलि का बकरा" खोजने की कवायद?

यदि चुनावी प्रबंधन में भी ऐसी ही "बुलेट ट्रेन जैसी त्वरित गति की "फुर्ती" दिखाई जाती, तो शायद परिणाम कुछ और होते।

दूसरी ओर कांग्रेस ने मतदान समाप्त होते ही, परिणाम आने से पहले ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। स्पष्ट है कि कांग्रेस नेतृत्व पूरे घटनाक्रम पर "बाज की नजर÷ रखे हुए था। विजयी प्रत्याशी ने भी "भीतरघात" की शिकायत पार्टी नेतृत्व से की थी।

भीतरघात: किसे कितना नुकसान ?

भीतरघात दोनों दलों में था, पर प्रकृति अलग थी।

भाजपा का "भीतरघात" चुनाव शुरू होते ही "चौराहे पर आ गया" और एक नैरेटिव व परसेप्शन बनकर सार्वजनिक विमर्श का विषय बन गया। वहीं कांग्रेस का भीतरघात संगठन की चारदीवारी के "भीतर" ही रहा।

पाठकों की बात — पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

हुआ सुदामा सा कभी,कब किसका सत्कार। कान्हा जैसा दूसरा,..हुआ नही फिर यार।। बना सुदामा मैं प्रभो,ज्ज्खोजूं सत्य चरित्र । कलियुग में भी श्याम सा, सीधा सच्चा मित्र ।। देख सुदामा मीत को , नजरे फेरें श्याम । बदल गये इस दौर में ,यारी के आयाम ।। जब यारी की नीवं ही,... नफा और नुकसान। चले नही ज्यादा दिवस ,उनकी कभी दुकान ।। रहे वहीं तक मित्रता, ...रहे वहीं तक प्यार जब तक हो व्यवहार में, शामिल नही उधार ।। मीत वही है ख़ास अब, है जो पूर्ण समर्थ । बदल गये हैं वाकई , अब यारी के अर्थ ।। लगे सामने यार के,अगर यार असहाय । यारी वो यारी नहीं, यारी वो व्यवसाय ।।

– रमेश शर्मा वशिष्ट

समय को पीछे छोड़ के आया समय को फिर भी आगे पाया समय बदलता पल-पल यारो मैं ही शायद बदल ना पाया। सोच-सोच कर आगे बढ़ता समय चले है, नहीं ठहरता चले चला चल रुक मत अब गया समय फिर नहीं लौटता।

– जे डी कुदाल

जश्न की रात थी जिंदगी बारात थी उनींदी पलकें,होंठों पे ठहरी बात थी गुजर गया हर लम्हा मुट्ठी के रेत सी रौशन दीवारें मगर वो गहरी रात थी।

– सपना चन्द्रा

लोग पोस्ट डालते हैं की हिन्दू मंदिर नहीं जाता लेकिन मंदिर में जो दो चार ट्रस्टी होते हैं जैसे लगता है मंदिर उनकी जागीर हो भगवान का घर सभी भक्तों के लिए एक समान होना चाहिए परन्तु प्रसाद देते समय मुंह देखकर प्रसाद देना बड़े मंदिरों की व्यवस्था आम नागरिक के लिए बहुत सारे नियम लेकिन वीआईपी लोगों के लिए सब सहज।

– सुनिल पुष्पराज पांडेय

तृषा कृष्णन पर भद्दे, डबल मीनिंग स्पीच पर उदयनिधि स्टालिन अरेस्ट हो गया.. गलती कर दी.. इसके बदले पीएम की माँ को गाली देता तो शाबाशी और माफी दोनों मिल जाती.. लिबरलों की वाह वाही मिलती वह अलग.. पहली बार आज जोसफविजय के लिए फुल सपोर्ट रहेगा..

– अंबर दानी

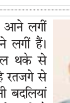

फिर गीत पुरवा आने लगीं हैं। बदली नगमे सुनाने लगीं हैं। ठहरे हैं टीलों पे बादल थके से जुगनू तो अब कर रहे रतजगे से वो नीली नीली सलोनी बदलियां रातों में पायल, बजाने लगीं हैं फिर गीत पुरवा... चूनर हवाओं में, लहरा रहीं हैं घटाएं मचलतीं कहाँ जा रहीं हैं रंगीली सजीली, महकती फिज़ाएं किसे ।गुनगुना कर,बुलाने लगीं हैं फिर गीत पुरवा...

– अजय कुमार सिंह भदौरिया

एक जगह वीडियो देख रही थी जिसमें ट्विंकल खन्ना आत्मश्लाघा से परिपूर्ण पूरे जोश और होशो-हवास में कह रही थी कि मेला फ़िल्म करने के बाद मैंने एक्टिंग से सन्यास ले लिया है,मुझे एक्टिंग में कोई खास रूचि नहीं है।इतना ही नहीं आगे कहते हुए गर्व से भावविभोर होकर कहती है कि एक ज्योतिष ने कहा था कि आप एक बेहतरीन उम्दा लेखिका बनेंगी और सच में बन गई। खैर!

– मधुबाला मौर्या

राशि फल

पं. देवव्रत शर्मा

मेष : आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल दायक है आज किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लाभ अथवा हानि के बारे में विचार अवश्य करें।

वृष: आज के दिन मध्यांन तक आप कर्म करने की अपेक्षा ख्याली पुलाव पकाएंगे। कार्य क्षेत्र पर काम काज होने के बाद भी मन अन्यत्र घूमेगा। परिवार के बुजुर्ग लंबी बीमारी के कारण परेशान होंगे।

मिथुन: आज परिस्थितियां कार्यों में बाधक बनेगी दिन के आरंभ से ही मन अनर्गल प्रवृतियों में भटकेगा बिना सोचे समझे किए गए कार्य बाद में पश्चाताप का कारण बनेंगे।

कर्क: आज के दिन परिस्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं फिर भी दिन के पूर्वार्ध में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जल्दबाजी में ना करें अन्यथा हानि होने की संभावना है।

सिंह: आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उसे ले देकर अवश्य ही संतोषजनक स्थिति तक पहुंचा देंगे। दिन के आरंभ में परिवार के बड़े लोग किसी महत्वपूर्ण विषय में आप का विरोध कर सकते हैं।

कन्या: आज का दिन आपके लिए सामान्य लेकिन आप के संपर्क में रहने वालों के लिए अति उत्तम रहेगा आज आप अपनी निजी आवश्यकताओं को अनदेखा कर परिजन एवं अन्य निकटस्थ लोगों की कामना पूर्ति करने के लिए समय एवं धन खर्च करेंगे।

तुला: आज का दिन आप के लिए परिश्रम सध्या ही रहेगा मध्यांन तक प्रत्येक कार्य में अधिक माथापच्ची करनी पड़ेगी लेकिन मध्यान्ह के बाद परिस्थितियां बेहतर बनने लगेंगी आज आप परिश्रम में कमी नहीं करेंगे।

वृश्चिक: आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है। आज आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे लेकिन स्वयं उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे।

धनु: आज के दिन आप पूर्व में की गई गलतियों में सुधार लाएंगे प्रत्येक कार्य सोच समझकर ही करेंगे फिर भी आप के संपर्क में आने वाले लोगों में आप की छवि जिद्दी इंसान जैसी बनेगी।

मकर: आज के दिन आपको अपनी वाणी एवं व्यवहार को संयमित रखने की आवश्यकता है मध्यांन तक किसी के द्वारा बोली गई।

कुंभ: आज का दिन आपके लिए धन लाभ वाला रहेगा। पूर्व में किए परोपकार एवं धार्मिक कार्यों का फल आज किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा।

मीन: आज के दिन आप का मन भ्रमित रहेगा मुख से कुछ बोलेंगे करेंगे उसका उल्टा ही।

QUIZ TIME

1) किस राज्य में स्थित ग्लॉ झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है?

2) किस देश द्वारा दुनियां का सबसे बड़ा सुपरकंडक्टिंग चुंबक बनाया गया है?

3) भारत में रेयर पृथ्वी तत्व के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है?

4) विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है?

5) किस राज्य के पारंपरिक पिथौरा चित्रकला को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है?

उत्तरमाला- (1) अरुणाचल प्रदेश (2) चीन (3) राजस्थान (4) 1-7 अगस्त (5) गुजरात

RamaQuiz

पहेली

शब्द सामर्थ्य -122

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 121 का हल

500 करोड़ रुपये से बदलेगी राज्य की डिजिटल तस्वीर : भाजपा

■ छत्तीसगढ़ में नई तकनीक व कौशल विकास का नया अध्याय

गरियाबंद/नवप्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 'छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन' को दी गई ऐतिहासिक मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति देने वाला एक दूरदर्शी निर्णय बताया है। चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश के डिजिटल रोडमैप को धरातल पर उतारने के नाम पर केवल जुबानी जमाखर्च किया जबकि भाजपा की साय सरकार का वास्तविक धरातल पर काम नजर आ रहा है।

भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का यह मिशन 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। यह मिशन न केवल बड़े शहरों तक सीमित रहेगा, बल्कि इसका मुख्य फोकस राज्य के दूर-दराज के जिलों, छोटे शहरों और कस्बों तक एआई की पहुँच सुनिश्चित करना है, ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे। इस योजना के मुख्य बिन्दुओं की चर्चा करते हुए

चंद्राकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन के तहत राज्यभर में अत्याधुनिक 100 एआई डेटा लैब का निर्माण किया जाएगा। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। युवाओं के नवाचार को बल देने के लिए 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के 6 लाख विद्यार्थियों तथा 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासकीय कामकाज को सुगम, पारदर्शी और तीव्र बनाने के लिए 50 से अधिक एआई-आधारित सेवाओं का विकास होगा।

भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा यह राग अलापते रहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पूरे देश को कम्प्यूटरीकृत करने का सपना देखा था। लेकिन सच्चाई यह है कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी सरकारों ने उनके सपनों को धरातल पर साकार करने की जरा भी पहल नहीं की। कांग्रेस ने तकनीक के नाम पर केवल बातें कीं, जबकि भाजपा की साय सरकार ने नीतियों को ज़मीन पर उतारकर यह साबित कर दिखाया है कि सुशासन और डिजिटल परिवर्तन कैसे लाया जाता है! चंद्राकर ने कहा कि यह मिशन भारत सरकार के 'इण्डिया एआई मिशन' के अनुरूप छत्तीसगढ़ को एक उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य-उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

शासकीय व गैर सरकारी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन जरुरी

ब ल ौ द ा ब ा ज ा र । शासकीय,अर्धशासकीय एवं प्राईवेट संस्थानों में जहां महिला कार्यरत हो अथवा नहीं हो सभी संस्थाओं में महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल प्रदान करने तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाए जाने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 की धारा 4 अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर भारत सरकार द्वारा सृजित शी -बॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड किया जाना अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। उच्चतम न्यायालय के प्रकरण तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली द्वारा लगातार सभी शासकीय,अर्धशासकीय एवं प्राईवेट संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति के गठन वहां प्राप्त प्रकरण तथा उसका निराकरण, वार्षिक रिर्पोट तथा कराये जाने एवं शी -बॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड किये जाने के लिए निर्देश दिये है। किसी भी शासकीय,अर्धशासकीय एवं प्राईवेट संस्थानो अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 26 अनुसार 50 हजार रूपये जुर्माना का भी प्रावधान है।

न्यूज गैलरी

'एबीसी' अभियान: 947 आवारा कुत्तों की नसबंदी, रेबीज से सुरक्षा की ओर कदम

कुरूद/नवप्रदेश। उच्चतम न्यायालय और एनिमल वेलफेयर बोर्ड

ऑफ इंडिया के निर्देशों के तहत धमतरी जिले के तीनों निकायों (नगर निगम धमतरी, नगर पालिका कुरूद और नगर पंचायत नगरी) में आवारा श्वानों के नियंत्रण के लिए 'एनिमल बर्थ कंट्रोल' (क्ष्ह्ट) अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा की 'स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसायटी' द्वारा संचालित इस अभियान में पशु चिकित्सकों की टीम श्वानों का स्वास्थ्य परीक्षण, नसबंदी, टीकाकरण और ऑपरेशन के बाद देखभाल कर रही है।

अभियान के मुख्य आंकड़े: धमतरी नगर निगम: 31 जुलाई तक 947 कुत्तों की सफल नसबंदी (573 नर और 374 मादा)।

नगर पालिका कुरूद: 29 स्ट्रीट डॉग्स का इलाज।

नगर पंचायत नगरी: 26 स्ट्रीट डॉग्स का इलाज।

कुरूद सीएमओ महेंद्र गुप्ता ने बताया कि नसबंदी के अलावा स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से अब तक सैकड़ों आवारा कुत्तों का टीकाकरण और डी-वॉर्मिंग भी किया जा चुका है। जिला प्रशासन के अनुसार इस सतत अभियान से न केवल आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी, बल्कि रेबीज जैसी घातक बीमारियों से बचाव और नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी

वीबी-जी.राम-जी अंतर्गत जिले की 476 ग्राम पंचायतों में 555 कार्य स्वीकृत

बलौदाबाजार/नवप्रदेश। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबी- जी राम जी के अंतर्गत जिला बलौदाबाजार ग्रामीण विकास एवं रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिले की कुल 519 ग्राम पंचायतों में से 476 ग्राम पंचायतों के लिए 555 विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत जिला प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों में श्रमिकों की मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसरों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जा रहा है। स्वीकृत कार्यों में जल सुरक्षा, जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत अधोसंरचना के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। विकासखंडवार बलौदाबाजार की 104 ग्राम पंचायतों में 139 कार्य, भाटापारा की 85 ग्राम पंचायतों में 105 कार्य, कसडोल की 111 ग्राम पंचायतों में 135 कार्य, पलारी की 72 ग्राम पंचायतों में 72 कार्य तथा सिमगा की सभी 104 ग्राम पंचायतों में 104 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शेष 43 ग्राम पंचायतों में भी कार्य स्वीकृति की प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ पूर्ण की जा रही है।

युवक ने लगाई फांसी, कारण अज्ञात ग्राम मोहड़ की घटना, मर्ग कायम

डोंगरगांव/नवप्रदेश। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहड़ में मंगलवार दोपहर एक 23 वर्षीय युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मोहड़ निवासी निवेन्द्र देवांगन (23 वर्ष) पिता खोमराज देवांगन ने मंगलवार 4 अगस्त को लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर के ऊपर बने टीन शेड में नायलॉन की रस्सी के सहारे फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में अफरातफरी मच गई। तत्काल आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर डोंगरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। घटनास्थल से किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की जानकारी नहीं है। पुलिस परिजनों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच जारी है।

नरेश आर्य दाल मिल एसोसिएशन के पुन: अध्यक्ष बने

भाटापारा/नवप्रदेश। दाल मिल एसोशिएशन के सदस्यों की हुई बैठक में सर्वसम्मति से एक बार पुनः नरेश आर्य के नाम पर सहमति जताते हुए उन्हें पुनः अध्यक्ष की बागडोर सौंप दी है। विदित हो कि वर्तमान अध्यक्ष नरेश आर्य का कार्यकाल पूरा हो गया और नए अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु एसोसिएशन की आयोजित बैठक में आम सहमति बनाने पर सभी एकमत होकर निर्णय लिए तथा सर्वसम्मति से उम्मीदवार तय करने का निर्णय लिया गया।बैठक में वरिष्ठ सदस्यों के सुझाव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताते हुए नरेश आर्य को पुनः दाल मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया।नरेश आर्य ने सभी सदस्यों के प्रति उन पर विश्वास जताने पर आभार व्यक्त किया था तथा विश्वास दिलाया कि पूर्व की भांति सभी की राय के अनुसार आगे के कार्य निरंतर रूप से आगे चलते रहेंगे। वही नरेश आर्य की पुनः नियुक्ति होने पर नगर के व्यवसायिक संगठन राइस मिल,पोहा मिल, दाल मिल,चैंबर आफ कॉमर्स,सहित अनेक संगठनों के सदस्यों ने उन्हें अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

झिझराकसा स्कूलों में पुस्तक आने के नाम पर स्कूलों में समय से पहले छुट्टी दे दी

गैर-जिम्मेदार शिक्षकों पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई : बीईओ

नगरी/नवप्रदेश। नगरी विकासखंड अंतर्गत वनां अंचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत झिझराकसा स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में बुधवार को निर्धारित समय से पहले विद्यार्थियों की छुट्टी किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शासन स्तर से कुछ विषयों की पाठ्यपुस्तकें विलंब से प्राप्त होने के कारण संकुल समन्वयक द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि प्रत्येक विद्यालय से केवल एक शिक्षक सीएसी/संकुल केंद्र घोटगांव पहुंचकर पुस्तकें प्राप्त करेगा।

बताया गया कि झिझराकसा के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में नई पाठ्यपुस्तकें लाने के नाम पर निर्धारित समय से पहले विद्यालय की छुट्टी कर दी गई। दोपहर लगभग 3 बजे विद्यालय पहुंचने पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं घर लौटते हुए दिखाई दिए। प्रतिनिधि के द्वारा पूछने पर विद्यार्थियों ने बताया कि शिक्षकों द्वारा छुट्टी दिए जाने के बाद वे घर जा रहे हैं। वहीं, विद्यालय में मौजूद शिक्षकों ने बताया कि पुस्तकें लेने जाने के कारण समयपूर्व छुट्टी की गई।

इस संबंध में पूछे जाने पर कुछ शिक्षकों ने बताया कि संकुल केंद्र घोटगांव में विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें लेने के लिए जाना था। इसी कारण विद्यार्थियों की छुट्टी पहले कर दी गई।

ग्राम पंचायत झिझराकसा के सरपंच ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षकों की समय-समय पर अनुपस्थिति की शिकायतें पहले भी सामने रही हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान भी कई बार शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। सरपंच ने शासन-प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कलीराम साहू ने कहा कि पुस्तक वितरण के नाम पर पूरे विद्यालय की समय से पहले छुट्टी करना विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों को पूर्व में ही निर्देशित किया गया था कि पुस्तकें लेने के लिए केवल एक शिक्षक जाएगा तथा विद्यालय का नियमित संचालन और शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

बीईओ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रतीत हो रहा है। मामले की जांच कराई जाएगी तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए तथा सभी विद्यालयों में निर्धारित समय तक नियमित शिक्षण कार्य संचालित करना अनिवार्य है ।

छुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई 4 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

छुरा/गरियाबंद/नवप्रदेश। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत छुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से गांजा लेकर बिक्री के उद्देश्य से जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा, मोटरसाइकिल और मोबाइल सहित कुल 2 लाख 35 हजार रुपये की सामग्री जब्त की है। पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के निर्देश पर जिलेभर में अवैध गांजा और शराब के परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना छुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक ष्ह्त 04 रूँ 2191 से अवैध गांजा लेकर बिक्री के लिए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कोसमबुड़ा चौक में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू की। कुछ ही देर बाद बताए गए नंबर की मोटरसाइकिल पहुंची, जिसे रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सफेद प्लास्टिक की बोरी में रखा 4 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

छुरा पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी को दबोचा

■ घर की परछी से चुराई थी बाइक, दूसरी बाइक की चाबी से दिया था वारदात को अंजाम

छुरा/नवप्रदेश। गरियाबंद पुलिस द्वारा अपराध एवं चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना छुरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइक बरामद कर ली है। आरोपी ने घर की परछी में खड़ी मोटरसाइकिल को पास में रखी दूसरी बाइक की चाबी से स्टार्ट कर चोरी करना स्वीकार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण एवं सक्रिय गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना छुरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।

प्रार्थी चमन लाल कुजाम, निवासी ग्राम कनसिंघी ने 1 अगस्त 2026 को थाना छुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक ष्ह्त 04 स्ब्क 9056 रात्रि में घर की परछी से अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर थाना छुरा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक संदेही से पूछताछ की गई।

पूछताछ में उसने अपना नाम गुलाब सिंह नागेश (35 वर्ष) निवासी कनसिंघी बोईरडीह थाना छुरा बताया। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने प्रार्थी के घर में खड़ी मोटरसाइकिल को पास में रखी दूसरी मोटरसाइकिल की चाबी से स्टार्ट कर चोरी की थी।

32 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

नया सवेरा अभियान के तहत छुरा पुलिस की कार्रवाई, आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

छुरा/नवप्रदेश। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे नया सवेरा अभियान के तहत छुरा पुलिस ने अवैध महुआ शराब के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,200 रुपये बताई गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के निर्देश पर जिलेभर में अवैध नशे के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना छुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम चरौदा में एक व्यक्ति अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री की तैयारी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बसंत नेताम (32 वर्ष), पिता जगत राम नेताम, निवासी महुआपारा वार्ड क्रमांक 10, ग्राम चरौदा, थाना छुरा, जिला गरियाबंद बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 32 लीटर अवैध कच्ची देशी महुआ शराब बरामद की गई, जिसे जब्त कर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध शराब, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सिद्धबाबा रेल्वे गेट आज से सोमवार तक रहेगा बंद

भाटापारा/नवप्रदेश। भाटापारा रेलवे मॉल धक्का के आगे भाटापारा एवं हथबंद रेलवे स्टेशनों के मध्य स्थित रेलवे समपार फाटक क्रमांक 385 (कि.मी. 766/14ङ्ग16), सिद्धबाबा रेल्वे गेट रेल लाइन में अत्यावश्यक मरम्मत कार्य के कारण उक्त समपार फाटक पर आज दिनांक 07 अगस्त, 2026 (शुक्रवार) प्रातः 09:00 बजे से दिनांक 10 अगस्त, (सोमवार) सायं 06:00 बजे तक सड़क यातायात का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। रायपुर रेल मंडल प्रशासन ने आमजन एवं वाहन चालकों से उक्त अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील करते हुए

आमजन को होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है तथा सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की है।

मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों को मिला भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र

धमधा/नवप्रदेश। 05 अगस्त को नगर पंचायत धमधा के सभाकक्ष में गरिमामय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) के अंतर्गत लाभान्वित 61 हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य पात्र नागरिकों को उनके सपनों का पक्का मकान वैध और सुगम तरीके से बनवाने के लिए प्रोत्साहित करना है । कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष श्वेता प्रशांत अग्रवाल व उपाध्यक्ष बृजेंद्र दानी व पार्षदगण एवं निकाय के कर्मचारी उपस्थित रहे । अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा की शासन की मंशा है, कि हर बेघर परिवार को सुरक्षित और सुसज्जित आवास उपलब्ध कराया जाए भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र मिल जाने से अब हितग्राही बिना किसी कानूनी बाधा के अपने आवास का निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे ।

कलेक्टर ने की स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा

प्रसव के दौरान 1 भी मातृ और शिशु की मृत्यु नहीं होनी चाहिए : कलेक्टर

■ बच्चों को फैलने वाले रोगों के मरीजों से दूर रखने पालकों को समझाने के निर्देश

सारंगढ़ बिलाईगढ़/नवप्रदेश। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने अप्रैल से जुलाई तक की स्थिति में स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का योजनावार, ब्लॉकवार डेटा की जानकारी लेकर सयुंक्त समीक्षा किया। बैठक में डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, ऋचा सिंह, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी,

डीपीएम, दोनों विभाग के सेक्टर सुपरवाइजर और सुपरवाइजर उपस्थित थे।

बैठक की शुरुआत में कलेक्टर ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। जिले में 1 भी मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर नहीं होनी चाहिए। दोनों विभाग के अधिकारी कर्मचारी आपस में समन्वय कर कार्य करें। यदि कोई मृत्यु हुई तो जांच होगी। किसी भी कर्मी की सेवा में कमी या लापरवाही हुई तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। हाईरिस्क प्रेग्नेंट महिला और उसके पति को प्रसव के समय आने वाली दिक्कत खून का बहाव, खून की कमी, सामान्य प्रसव या ऑपरेशन से प्रसव आदि स्थिति के बारे में समझाए और प्रसव पीड़ा या गर्भ का समय पूर्ण होने की स्थिति में नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराएं।

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने पोषण पुनर्वास केंद्र में अब तक सुपोषित बच्चों की स्थिति की जानकारी लेकर कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग कुपोषित बच्चों का चयन कर पोषण पुनर्वास केंद्र भेजें, वहीं दर्ज बच्चों को सारी सुपोषण दवा और पोषक आहार प्रदान करें।

कलेक्टर ने जिले में पुराने और नये टीबी मरीजों की जानकारी सुपरवाइजरों से लेकर निर्देश दिए कि, सभी अपने क्षेत्र के टीबी मरीजों को समझाये कि, वे जब किसी व्यक्ति के आसपास मौजूद होते हैं तो वे मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि टीबी और कुष्ठ रोग दोनों एक दूसरे के माध्यम से फैलता है इसलिए बच्चों सहित अन्य लोग खानपान में सावधानी रखें। टीबी और कुष्ठ बीमारी को खत्म करने के लिए सभी घरों में बीमार व्यक्ति से बच्चों को दूर रखें, जिले में 8 बच्चों को कुष्ठ बीमारी के लक्षण पाए गए हैं।

कुष्ठ बीमारी के लक्षण आने में 3 से 5 साल का समय लगता है। कलेक्टर ने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए 15 वर्ष के बालिकाओं और अन्य इच्छुक महिलाओ को एचपीवी वैक्सीन लगाने के लिए पालकों को प्रेरित करें। कलेक्टर ने पीएम बाल संदर्भ चिरायु और पीएम मातृ वंदना योजना के अब तक हुए शिविर की जानकारी लेकर कहा कि पीएम मातृ वंदना योजना के अब तक 1883 को लाभ मिला है ।

नए मकान में बिजली कनेक्शन लगवाने के दौरान विवाद, दो पर मामला दर्ज

महासमुंद/नवप्रदेश। पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गिरना में नए मकान में बिजली कनेक्शन लगवाने के दौरान हुए विवाद में दो लोगों द्वारा एक व्यक्ति से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम गिरना निवासी सुरेश विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई कि 4 अगस्त को वह अपने नए मकान में बिजली कनेक्शन लगवा रहा था। इसी दौरान गांव के त्रिलोचन गड़तिया और लोकनाथ बरिहा वहां पहुंचे और बिजली कनेक्शन को लेकर विवाद करते हुए गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की।

संक्षिप्त खबरें

रेस्टोरेंट, स्वीट्स एवं ढाबा होटल संचालक संघ का हुआ गठन, सर्वसम्मति से बनाए पदाधिकारी

नवापारा राजिम/नवप्रदेश। रेस्टोरेंट एवं होटल से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर मैडम ज्योति भानु एव सहायक कालेश्वर यादव के द्वारा राजिम के संपूर्ण होटल एव रेस्तरां के संचालनकर्ता की उपस्थिति में आवश्यक मीटिंग रखा गया। मीटिंग पश्चात सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा एक समूह की स्थापना की गई जिसमें अध्यक्ष के रूप में सुमित भोजनालय के संचालक रामकुमार गोस्वामी, उपाध्यक्ष राजीव लोचन होटल के संचालक सुनील देवांगन, कोषाध्यक्ष समीम वारसी लाजीज बिरयानी, सचिव बाबू भाई बिकानेर स्वीट्स, सहसचिव मुकुल कंसारी बंटू होटल संचालक को सर्व सम्मति से मनोनीत किया गया। इस बैठक में विशेष रूप से सुनील देवांगन, महेश साहू, प्रद्युम्न देवांगन, उमेश यादव, अभिनव गुप्ता, अभिजीत देवांगन, हरीश देवांगन, सागर, हितेश साधवानी, सागर अमर मिष्ठान, ताराचंद, राजा सोनी, राजेश साहू, लेखा महोबिया, संतोष, नवीस अली, शम्मु अली, जीवन कंडरा, बल्लू कंसारी एवं समस्त सदस्य रेस्टोरेंट स्वीट्स ढाबा होटल की उपस्थिति रही।

मध्य प्रदेश व बिहार उपचुनाव परिणामों से भाजपा का पतन होने का श्रीगणेश :लक्ष्मी ध्रुव

नगरी/नवप्रदेश। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने मध्य प्रदेश एवं बिहार के उपचुनाव परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि इन चुनाव परिणामों से यह संकेत मिलता है कि भाजपा के प्रति जनता का विश्वास धीरे-धीरे कम हो रहा है।

उन्होंने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की जीत का स्वागत करते हुए कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को राजनीतिक साजिश के तहत हराने का प्रयास किया गया, लेकिन उपचुनाव के परिणाम भाजपा के लिए बड़ा झटका साबित हुए।

पूर्व विधायक ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भाजपा प्रत्याशी को 18,953 मतों के अंतर से पराजित किया, जिससे भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर प्रश्नचिह्न खड़ा हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में कांग्रेस दिल्ली, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी मजबूत वापसी करेगी।

श्री चिन्मय सागर महाराज का जन्म दिवस भाटापारा में धूमधाम से मनाया

भाटापारा/नवप्रदेश। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भाटापारा में श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा का 65 वा जन्म दिवस भाटापारा में धूमधाम से मनाया गया । प्रात काल महावीर भगवान का जन्म अभिषेक महोत्सव, शांति धारा, आरती संपन्न की गई। स्थानीय मंदिर में चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा का मूल सिंहासन जिस पर महाराज जी बैठते थे, और महाराज जी को खड़े करके उनके मूल चरण बनाए गए थे, 2010 में शिवपुरी के जंगलों में, वह मुख्य चरण भी यहां विराजमान है। उन चरणों का आज चरण अभिषेक जल, दूध ,केसर ,चंदन, हल्दी के माध्यम से संपन्न हुआ। उसके पश्चात रत्न वृष्टि एवं पुष्प वृष्टि संपन्न हुई।उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर जंगल वाले बाबा चिन्मय सागर जी महाराज की भक्ति भाव से अष्ट द्रव्य से पूजन की। वही श्री चिन्मय सागर विद्या निकेतन बोरतरा में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ ,वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूल के समस्त टीचर स्टाफ बच्चे ,जैन समाज के श्रावक, मोदी परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे ।उसके पश्चात सरकारी अस्पताल एवं आडील हॉस्पिटल में मरीजों को बिस्किट एवं फल वितरण किया गया तथा रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों को पूड़ी सब्जी एवं पुलाव का वितरण किया गया।

गुडरूपारा के 150 गरीब परिवारों ने भू-स्वामी पट्टे की लगाई गुहार

महासमुंद/नवप्रदेश। शहर के वार्ड क्रमांक 18 स्थित गुडरूपारा तालाब के समीप शासकीय भूमि पर झोपड़ी बनाकर वर्षों से निवास कर रहे गरीब परिवारों ने विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा से मुलाकात कर भू-स्वामी पट्टा जारी करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए जमीन का मालिकाना हक दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड क्रमांक 18 के गुडरूपारा तालाब के पास स्थित खसरा क्रमांक 1543 की शासकीय भूमि पर लगभग 150 परिवार लंबे समय से निवास कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा कब्जाधारी परिवारों का सर्वे कर उन्हें मालिकाना हक देने की योजना संचालित की जा रही है, ऐसे में उन्हें भी इसका लाभ प्रदान किया जाए। निवासरत परिवारों ने बताया कि वर्ष 1984 में सरकार द्वारा कुछ परिवारों को पट्टा प्रदान किया गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में भूमि का स्वामित्व नहीं होने के कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित हैं। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित निराकरण का आश्वासन दिया।

कांग्रेस में टला बड़ा सियासी संकटः संध्या राव का इस्तीफा नामंजूर, नेता प्रतिपक्ष पद पर रहेंगी बरकरार

नवापारा-राजिम/नवप्रदेश। नगर पालिका परिषद नयापारा की नेता प्रतिपक्ष संध्या राव द्वारा दिए गए इस्तीफे को कांग्रेस संगठन ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष पप्पू बंजारे की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापक मंथन के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संध्या राव को नेता प्रतिपक्ष के पद पर पूर्ववत कार्य करने दिया जाए।

जारी आदेश के अनुसार, 26 जुलाई 2026 को जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण कार्यालय, गांधी भवन, रायपुर में

जिला कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संध्या राव ने अपने इस्तीफे के संबंध में अपना पक्ष रखा।

बैठक में पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने संगठनात्मक एकता, अनुशासन एवं सामूहिक निर्णय की महत्ता पर बल देते हुए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नयापारा के अध्यक्ष रामा यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा, राजा चावला, कांग्रेस पार्षद अजय साहू, अर्जुन साहू, तरुण कंसारी, ब्लॉक पदाधिकारी मितेश शाह, सुरेंद्र साहू सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा हुई। वहीं वरिष्ठ नेता धनराज मध्यानी, जीत सिंह एवं शेखर बाफना से दूरभाष पर भी राय ली गई।

बैठक में उपस्थित नेताओं तथा नगर पालिका परिषद नयापारा के 9 में से 7 कांग्रेस पार्षदों ने व्यक्तिगत एवं टेलिफोनिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से मत व्यक्त किया कि संध्या राव पार्टी की सक्रिय महिला नेत्री हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने से कांग्रेस संगठन को राजनीतिक एवं संगठनात्मक नुकसान हो सकता है। इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य जारी रखने दिया जाए।

आदेश के अनुसार, वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद संध्या राव ने भी कांग्रेस की विचारधारा, नेतृत्व एवं संगठन के प्रति अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी हित में अपने इस्तीफे के निर्णय पर पुनर्विचार किया तथा कांग्रेस के साथ पूर्ववत कार्य करते रहने की लिखित सहमति दी।

बताया गया कि बैठक के सर्वसम्मत निर्णय से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री (संगठन) मलकीत सिंह गैन्दू को भी व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया गया। उनके मार्गदर्शन एवं बैठक में बनी सर्वसम्मति के आधार पर आदेश जारी किया गया।

आदेश के प्रमुख बिंदु

संध्या राव द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता। संध्या राव नगर पालिका परिषद नयापारा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर पूर्ववत कार्य करती रहेंगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नयापारा संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच सामूहिकता और समन्वय से कार्य करना सुनिश्चित करेगी। इस निर्णय के साथ नयापारा कांग्रेस में इस्तीफे को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है और संगठन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आंतरिक मतभेदों का समाधान संवाद और सामूहिक निर्णय के माध्यम से किया जाएगा।

जिले की तीन जलाशय परियोजनाओं के लिए मिली 11 करोड़ राशि की स्वीकृति

गनियारी जलाशय, पतोरा नहर लाइनिंग और ठाकुरदेव जलाशय का होगा कायाकल्प

■ **विधायक रोहित साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिया धन्यवाद**

राजिम/नवप्रदेश। राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू के सतत प्रयासों से जिले की सिंचाई परियोजनाओं के विकास हेतु करोड़ों रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा गरियाबंद जिले की तीन प्रमुख जलाशयों एवं व्यपवर्तन योजनाओं के जीर्णोद्धार, मरम्मत एवं नहर लाइनिंग कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपये से अधिक 1104.23 लाख रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इस स्वीकृति से क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को सीधा लाभ मिलेगा और अंतिम छोर के खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँच सकेगा। इन स्वीकृत कार्यों में पतोरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य हेतु 202.50 लाख रुपए, गनियारी जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का

जीर्णोद्धार, वेस्ट वियर व्यर्थ जल निकास की मरम्मत, मुख्य नहर की रिमॉडलिंग एवं सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग कार्य के लिए 466.00 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है जिससे 144 हेक्टेयर से अधिक रकबा कृषि भूमि लाभान्वित होगी। इसके अलावा ठाकुरदेव जलाशय योजना शीर्ष तथा मुख्य नहर एवं शाखा नहरों का जीर्णोद्धार, मरम्मत व नहर लाइनिंग कार्य 435.73 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं जिससे 80 हेक्टेयर से अधिक रकबा लाभान्वित होगा।

इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विधायक रोहित साहू ने कहा कि हमारा राजिम विधानसभा क्षेत्र और संपूर्ण गरियाबंद जिला कृषि प्रधान क्षेत्र है। अन्नदाता का सम्मान और उनकी खुशहाली ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। जब-जब खेतों तक पानी पहुँचने में बाधा आई है, हमने किसानों के हित में कार्य किया है। आज गनियारी, ठाकुरदेव और पतोरा जैसी सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार व नहरों के सुदृढ़ीकरण की जो स्वीकृति मिली है, वह हमारे हजारों किसानों के सपनों और मेहनत को नया जीवन देने का संकल्प है।

नहरों के सीमेंट लाइनिंग से पानी का अपव्यय रुकेगा और अंतिम छोर पर खड़े किसान के खेत तक भी आसानी से पानी पहुँचेगा। जब खेत लहलहाएंगे, तभी हमारा क्षेत्र समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। विधायक रोहित साहू ने इस जनहितैषी और किसान हितैषी निर्णय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का राजिम एवं गरियाबंद क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद व आभार व्यक्त किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की सुशासन की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी को धरातल पर उतार रही है। हमारी सरकार ने तत्काल बजटीय स्वीकृति देकर यह साबित कर दिया है कि यह सरकार किसानों के हितों के प्रति कितनी संवेदनशील है। मैं मुख्यमंत्री जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी माँग को प्राथमिकता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की।

वर्षों पुरानी नहरों के जर्जर होने के कारण सिंचाई संकट से जूझ रहे क्षेत्रीय किसानों ने इस स्वीकृति पर अपार हर्ष व्यक्त किया है। गनियारी, पतोरा और ठाकुरदेव क्षेत्र के ग्रामीणों एवं किसान संघों ने लोकप्रिय रोहित साहू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सजग नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के कारण ही इतने बड़े स्तर पर बजट स्वीकृत हो पाया है।

अवैध प्रवासियों एवं किरायेदारों के सत्यापन अभियान के तहत पुलिस की कार्यवाही

गरियाबंद/नवप्रदेश। पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के निर्देशन में जिलेभर में अवैध प्रवासियों, बाहरी फेरीवालों एवं किरायेदारों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना देवभोग पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों से आए फेरीवालों तथा किरायेदारों का सघन सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान संबंधित व्यक्तियों के आधार कार्ड का एम-आधारऐप के माध्यम से सत्यापन किया गया।

साथ ही उनके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मोबाइल फोन कॉल एवं व्हाट्सएप कॉल हिस्ट्री का परीक्षण कर यह भी जांच की गई कि कहीं किसी प्रकार के अंतरराष्ट्री नंबरों से संपर्क तो नहीं है, इस पर भी चेक किया गया। सत्यापन उपरांत सभी संबंधित व्यक्तियों का थाना स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों का मिलान कर नेफिस प्रणाली में बायोमेट्रिक एवं अन्य आवश्यक प्रविष्टियां भी की गईं।

गरियाबंद पुलिस आम नागरिकों, मकान मालिकों एवं ग्रामवासियों से अपील करती है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई बाहरी व्यक्ति, किरायेदार अथवा फेरीवाला निवास या कार्य कर रहा हो, तो उसका सत्यापन निकटतम थाना में अवश्य कराएं तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना टोल फ्री नम्बर 1800 233 1905 या पुलिस को दें।

साइकिल के पहियों पर दौड़ेंगे अब बेटियों के सपने, शिक्षा के सफर को मिला नया सहारा

गरियाबंद/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत गुरुवार को स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, गरियाबंद में कक्षा नवमी की 27 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। योजना का उद्देश्य दूर-दराज़ के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना तथा ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना है।

इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष आशीफ मेमन ने कहा कि राज्य सरकार की यह योजना छात्राओं के लिए बेहद उपयोगी है। साइकिल मिलने से दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को नियमित रूप से विद्यालय आने में सुविधा होगी, जिससे उनकी शिक्षा बाधित नहीं होगी। उन्होंने छात्राओं से साइकिल का सदुपयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

वहीं पार्षद सुरेंद्र सोनटेके ने कहा कि बेटियों की शिक्षा समाज के विकास की सबसे बड़ी आधारशिला है। सरकार द्वारा दी जा रही यह सुविधा छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देगी। उन्होंने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने परिवार व जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दीं।

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार योजना के अंतर्गत कक्षा नवमी की अनुसूचित जाति की 3, अनुसूचित जनजाति की 4 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बीपीएल वर्ग की 20 छात्राओं सहित कुल 27 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य दीपक कुमार बौद्ध सहित नरगिस कुरैशी, भेलेश्वरी कोमर्रा, किशोर कुमार साहू, कल्पना पटेल, कमलेश असरानी, सुजाता राणा, महिमा तिर्की, किरणनंद, देवमाया पाल, वागेश्वरी कुंजाम, समीक्षा कुशवाहा, डागेश्वरी साहू, कैलाश कोसरे, सिम्मी विल्सन, धर्मेंद्र मार्टल, रोशनी साहू, त्रिलोचना साहू, तेजस्वी दाऊ, केवरा ध्रुव, लोकेश साहू, हेमंत सिन्हा एवं विद्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने चलाया सघन जांच अभियान

एनालॉग पनीर निर्माण व विक्रय प्रतिबंधित

बलौदाबाजार/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी हालिया प्रतिषेध आदेश के तहत राज्य में फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स्ड फेट स्प्रेड जैसी मानकीकृत श्रेणियों को छोड़कर असली पनीर की नकल करने बाले सभी वनस्पति वसायुक्त गैर-दुग्ध एनालॉग पनीर के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा डेयरी एवं दुग्ध संग्रहण केन्द्रों का सघन निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है।

बुधवार को भाटापारा के विभिन्न प्रतिष्ठानों में एनालॉग पनीर की उपलब्धता की सघन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान लाल बहादुर शास्त्री बार्ड, पटपर स्थित नर्मदा दूध संकलन केंद्र की भी जांच की गई, जहां परिसर में स्वच्छता संबंधी कमियां पाई गई। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत प्रतिष्ठान को कड़ी चेतावनी के साथ सुधार नोटिस जारी किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और डेयरी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे असली डेयरी पनीर के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का कृत्रिम या एनालॉग पनीर न परोसें।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार, जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा भाटापारा शहर में एक विशेष आई.ई.सी.गतिविधि का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छ, सुरक्षित और मानक ग्तर के खाद्य पदार्थों के विक्रय के प्रति जागरूक करना था। अभियान के दौरान साथ सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने भाटापारा शहर के विभिन्न मुख्य बाजारों, मिष्ठान भंडारों, डेयरी दुकानों, किराना स्टोर्स और होटल संचालकों से सीधा संपर्क किया। अधिकारियों ने कारोबारकर्ताओं को खाद्य गुरक्षा से संबंधित विशेष रूप से तैयार किए गए सूचनात्मक पंपलेट वितरित किए और उनका बारीकी से अध्ययन कराया।सभी विक्रेताओं को अपनी कमियों को तुरंत मुधारने की सलाह दी गई है, ऐसा न करने पर भविष्य में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी का नगरी के विद्यालयों में सघन निरीक्षण

शैक्षणिक गुणवत्ता, परीक्षा परिणाम और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति पर दिया जोर

नगरी/नवप्रदेश। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने विकासखंड नगरी के विभिन्न विद्यालयों का सघन निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों एवं प्राचार्यों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप पाठ्यक्रम पूर्ण कराने, नियमित मूल्यांकन तथा बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित

करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरेगांव में मासिक परीक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, विषयवार अध्यापन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति की समीक्षा की गई। अनियमित विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा ब्लूप्रिंट के अनुरूप परीक्षा तैयारी कराने के निर्देश दिए गए।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरगुड़ी में उपचारात्मक कक्षाओं के संचालन, विद्यालय विकास योजना और विषयवार अध्यापन की समीक्षा की गई। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान संध्या प्रार्थना सभा नियमित नहीं होने की जानकारी मिलने पर प्राचार्य को इसे तत्काल नियमित कराने के निर्देश दिए गए।

नगर पालिका की सामान्य बैठक में जनहित के कई अहम फैसले

महासमुंद/नवप्रदेश। नगर पालिका परिषद महासमुंद की सामान्य बैठक गुरुवार को नगर पालिका सभाकक्ष में अध्यक्ष निखिलकांत साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर के समग्र विकास, जनसुविधाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।

बैठक की शुरुआत मुख्य नगर पालिका अधिकारी सौरभ शर्मा ने परिषद के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के स्वागत उद्बोधन के साथ की। इसके बाद विभिन्न एजेंडों पर चर्चा करते हुए परिषद ने जनहित से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भाटापारा की बैठक सम्पन्न जनआंदोलन को मजबूत बनाने हुआ निर्णय

भाटापारा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बढ़े हुए बिजली बिल एवं स्मार्ट मीटर के विरोध में चलाए जा रहे फार्म भरने के अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ब्लाक कांग्रेस ग्रामीण की बैठक अध्यक्ष अमर मंडावी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अभियान को गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक पहुंचाने तथा अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।प्रदेश प्रतिनिधि सुनील माहेश्वरी ने कहा की ÷ ई वी एम मशीन की तरह स्मार्ट मीटर भी गलत रीडिंग कर रही है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की

अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा धृतलहरे ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आम जनता लगातार बढ़ते बिजली बिलों से परेशान है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ रही है और स्मार्ट मीटर तथा बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चला रही है।

विधायक इन्द्र साव ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई और बढ़ते बिजली बिलों की दोहरी मार झेल रही है। भाजपा सरकार जनता को राहत देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्षरत है और यह अभियान उसी संघर्ष का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित, लोक कलाकारों को मिलेगा सम्मान और आर्थिक संबल

लोक कलाओं के संरक्षण की दिशा में संस्कृति विभाग की अभिनव पहल

■ चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष 12 हजार से 24 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि, 31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

कवर्धा / नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की समृद्ध लोक कला, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रभावी पहल कर रही है। इसी कड़ी में संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस महत्वाकां योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित करना, लोक कलाकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उनकी कला को नई पहचान दिलाना तथा सांस्कृतिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।

योजना के अंतर्गत लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीत लेखन, पारंपरिक वाद्ययंत्र वादन, शिल्प कला, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक पाक कला तथा छत्तीसगढ़ी सौंदर्य कला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। योजना के माध्यम से लोक कलाकारों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप प्रोत्साहन प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे अपनी कला का संरक्षण एवं संवर्धन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

योजना के तहत पात्र कलाकारों का 'चिन्हारी पोर्टल' में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार दी जाएगी, जिससे कलाकारों को अपनी कला के संरक्षण और प्रस्तुति के लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। योजना का लाभ ऐसे कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, सेक्टर-27, नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)-492018 के पते पर भेजे जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय के कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026' स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने इस योजना के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और लोक कलाओं के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि यह उन लोक कलाकारों के सम्मान और स्वाभिमान को सशक्त करने का माध्यम है, जिन्होंने पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखा है।

न्यूज गैलरी

लंबे समय से फरार चल रहे 05 स्थायी वारंटी बेरला पुलिस के गिरफ्त में

बेमेतरा/नवप्रदेश। बेमेतरा पुलिस द्वारा स्थायी वारंटियो को पकडने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं। इसी क्रम में आज 06 अगस्त को* थाना बेरला पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट में अपराध क्रमांक 153/2021, धारा 341,395,120क्ष भादवि के प्रकरण में फरार चल रहे 05 स्थायी वारंटियों 01. महेश यादव पिता लेखराम यादव उम्र 21 वर्ष, 02. नागेश्वर यादव ऊर्फ शाहूत पिता सुरेन्द्र यादव उम्र 22 वर्ष, 03. त्रयंक यादव ऊर्फ राजा पिता प्रवीण यादव उम्र 22 वर्ष, 04. शेखर डहरिया ऊर्फ मोन्टू पिता सुखनंदन डहरिया उम्र 22 वर्ष, 05. ठाकेन्द्र यादव ऊर्फ बब्लू पिता सुरेन्द्र यादव उम्र 21 वर्ष, सभी निवासी धरसीवा जिला रायपुर को पकड़ा गया। जिसे माननीय न्यायालय में स्थाई वारंट तामील कर प्रस्तुत किया गया।उक्त कार्यवाही में* थाना प्रभारी बेरला उप निरीक्षक राजकुमार साहू, प्रधान आरक्षक दीनानाथ यादव, आरक्षक संजय पाटिल सहित थाना बेरला के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

संगीत विवि में पंडवानी की पुरोधा तीजन बाई को श्रद्धांजलि

खैरागढ़ / नवप्रदेश। इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो.डॉ. लवली शर्मा की अध्यक्षता में पद्मविभूषण स्वर्गीय तीजन बाई को समर्पित सांगीतिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडवानी की वेदमती एवं कापालिक शैली की प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से महान लोकगायिका तीजन बाई को श्रद्धाजंलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री उषा बारले ,अतिथि चेतन देवांगन, रम्भा बाई देशमुख, सावित्री पारधी, रेडु देशमुख, आलिम बंशी, केवल देशमुख, चैतराम साहू, रामचंद निषाद, नरोत्तम निषाद तथा तीजन बाई के वरिष्ठ संगतकार डालेश्वर निर्मल विश्वविद्यालय के कुलसचिव वेंकटरमन गुड़े, लोकसंगीत विभाग अधिष्ठाता राजन यादव, संगीत संकाय अधिष्ठाता प्रो. डॉ. नमन दत्त सहित विश्वविद्यालय परिवार की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण सुप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ युवा पुरस्कार से सम्मानित तथा संस्कृति मंत्रालय की संस्था सांस्कृतिक स्त्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र से जूनियर फेलोशिप अवार्ड प्राप्त दुष्यंत द्विवेदी की प्रस्तुति रही। उन्होंने वेदमती शैली में द्रौपदी स्वयंवर का सजीव एवं प्रभावशाली गायन प्रस्तुत कर अपनी विशिष्ट शैली से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुष्यंत द्विवेदी देश के विभिन्न प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में गुवाहाटी एवं सिलचर असम, रंग स्वाधीनता नई दिल्ली, अमृत स्वरधारा युवा उत्सव सूरत, गुजरात, महाराज कुमारी विनोदिनी देवी समारोह इम्फाल, मणिपुर, प्रयागराज महाकुंभ के कलाग्राम मुंबई फिल्म सिटी तथा कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन के निवास पर प्रस्तुति दे चुके हैं। बिलासपुर निवासी वरिष्ठ पंडवानी गायिका दूजन बाई ने कापालिक शैली में द्रौपदी चीरहरण प्रसंग की मार्मिक प्रस्तुति दी। दूजन बाई देश के अनेक राज्यों तथा छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान रखती हैं।

धनेली,देवारीभाठ, बढ़ईटोला सड़क निर्माण के लिए 17 करोड़ की स्वीकृति

खैरागढ़ / नवप्रदेश। ग्रामीण अंचलों में आवागमन को सुगम बनाने मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने खैरागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले धनेली से देवारीभाठ, भरदाकला व्हाया बढ़ईटोला 10 किलोमीटर तक बनने वाली पक्की सडक़ के निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सडक़ के निर्माण से दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को अब खराब सडक़ों की समस्या से मुक्ति मिलेगी। देवारीभाठ सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह से इस मार्ग के नए निर्माण के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इस मांग को लेकर विक्रांत सिंह ने शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए। उनके प्रयासों के बाद 17 करोड़ रुपये सडक़ निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है। धनेली से देवारीभाठ, भरदाकला,बढ़ईटोला तक का यह मार्ग क्षेत्र का एक प्रमुख संपर्क मार्ग है। पक्की सडक़ बन जाने से धनेली, देवारीभाठ, भरदाकला और बढ़ईटोला सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों, किसानों और स्कूली बच्चों को आने-जाने में बहुत सुविधा होगी। इसके अलावा, बारिश के दिनों में कीचड़ और गड्ढों से होने वाली हादसों की आशंका भी खत्म हो जाएगी।

सड़कों पर मवेशियों के झुंड से हादसे बढ़ रहे, खेतों में घुसकर फसल कर रहे चट

■ कलेक्टर के आदेश का असर नही

■ ग्रामीणो ने कलेक्ट्रेट पहुँच राहत दिलाने सौंपा ज्ञापन

खैरागढ़ / नवप्रदेश । सडक़ो पर बैठने वाले मवेशियो से हो रही परेशानियों को लेकर पिपरिया वार्ड से लेकर अमलीडीह, टेकापार, कातलवाही, भूलाटोला, दिलीपपूर, खमतराई के किसानो ने कलेक्ट्रेट पहुँच कर ज्ञापन सौंप मवेशियो से राहत दिलाने की मांग की है । ग्रामीणो ने ज्ञापन मे कहा कि पिछले कई महीनो से राजनांदगांव कवर्धा स्टेट हाइवे मे शहर के राइसमिल से भूलाटोला तक बड़ी संख्या मे आवारा और निराश्रित मवेशियो के बैठने से जहाँ रोजाना दुर्घटनाएं सामने आ रही है । तो रात मे इन मवेशियो द्वारा धान की फसलो को खेतो मे घुस कर नुकसान पहुँचाया जा रहा है । किसान विपरीत परिस्थितियों मे धान की फसल लगा रहे है । बीज, दवाई,मजदूरी सहित कई खर्चो के बाद लगाए जा रहे फसलो को आवारा मवेशियो द्वारा रोजाना नुकसान पहुँचाया जा रहा है । इससे किसानो को आर्थिक परेशानियो के साथ साथ फसल का नुकसान उठाना पड़ रहा है । किसानो को दिनभर मेहनत के बाद रात भर खेतो की रखवाली भी करनी पड़ रही है । मवेशियो की समस्या पर कार्यवाही नही होने से अब गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है । किसानो ने मुख्य मार्ग मे भुलाटोला तक सडक़ पर बैठने वाले मवेशियो की समुचित व्यवस्था करने प्रबंधन पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग करते कहा कि मवेशियो से राहत नही मिली तो दुर्घटनाओ मे बढ़ोत्तरी के साथ साथ किसानो को फसल क्षति का आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा ।

साल भर से आदेश सिर्फ कागजो में

शहर सहित ग्रामीण इलाको मे सडक़ो को आवारा मवेशियो से खाली कराने, फसलो की सुरक्षा सहित अन्य मामलो को लेकर कलेक्टर पिछले साल भर से शहर निकाय और पंचायत अधिकारियो को हर समयसीमा की बैठक मे समुचित व्यवस्था के निर्देश दे रहे है । लेकिन साल भर से इसमें अधिकारियो नें किसी प्रकार का अमल नही किया । शहर की सडक़ो से मवेशियो को हटाने गौठान,गौशालो मे व्यवस्था बनाने के निर्देश नगरपालिका अधिकारियो को दिए गए है । जबकि ग्रामीण क्षेत्रो मे फसलो और सउक़ो को मवेशियो से बचाने जनपद अधिकारियो को व्यवस्था बनाने कहा गया था लेकिन समयसीमा की बैठक मे अधिकारी निर्देशो के पालन का हवाला दे रहे है । अब तक मामले मे ठोस कार्यवाही नही हो पाई है । इसके चलते इस साल भी सडक़ो पर मवेशियो के डेरे से रोजाना हादसे बढ़ रहे है । फसलो को भी खेतो मे घुस कर मवेशी नष्ट कर रहे है । ग्रामीणो ने अब जमीनी स्तर पर मवेशियो की व्यवस्था बनाने की मांग की है ।

सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

■ जिले के विभिन्न सड़कों के उन्नयन की मांग

कवर्धा / नवप्रदेश। क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने दिल्ली में केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 अंतर्गत धंवई (छग-मप्र बार्डर) से कवर्धा होते हुए सिमगा तक फ़ोरलेन सड़क निर्माण, कवर्धा से खैरागढ़ तक सड़क मजबूती व चौड़ीकरण व कवर्धा में नया बायपास सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने की मांग को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को पत्र सौंपा।

सांसद संतोष पांडेय ने केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 अंतर्गत धंवई (छग-मप्र बार्डर) से कवर्धा होते हुए सिमगा तक फ़ोरलेन सड़क निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है। जिसकी लंबाई कुल 125 किमी है यह मार्ग छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश दोनों राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। यहां से कई राज्यों के बड़े छोटे वाहनों का आवागमन होता है। चिल्फी घाटी में आए दिन घंटों लंबा जाम लगता है। इसके चलते आवागमन बाधित होता है। राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग में फोरलेन सड़क का निर्माण हो जाने से आवागमन सुगम हो जाएगा।

सांसद पांडेय ने कवर्धा से खैरागढ़ तक सड़क मजबूती व चौड़ीकरण की आवश्यकता है। यह कबीरधाम से खैरागढ़ होते हुए राजनांदगांव जिले को जोडने वाली एकमात्र सड़क है। जो जर्जर व खराब हो चुकी है।

न राह आसान न किसानी हर कदम पर परेशानी घुमंतू पशु बने मुसीबत

बेमेतरा/नवप्रदेश। जिले में एक भी ऐसी सड़क नही जिसमे बेधड़क यात्रा की जा सके, जिले के अंतिम छोर पर बसे ग्राम पंच भैया में फोक नदी पर बने ब्रिज की तस्वीर से यह प्रतीत होता है कि गांव का गौठान है, ब्रिज के एक किनारे में सूखे गोबर साबित कर रहे हैं कि बसेरा स्थाई है, पंच भैया से दाढ़ी, दाढ़ी से उमरिया, बेमेतरा से नवागढ़ , नवागढ़ से चारो दिशाओ की सड़क पर हरेक गाँव में कम से कम चार जगह मवेशियों का जमावडा आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, हाईकोर्ट की फटकार के बाद उम्मीद थी कि कुछ सुधार होगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिले के अधिकारी यदि बाइक से एक बार भ्रमण कर ले तो उन्हें आम आदमी की मुसीबत समझ आ जाएगा,

फसल चराई से किसान आहत

किसान नेता जितेन्द्र सिंह भुवाल ने कहा कि हरेक गांव में घुमंतू पशुओं के कारण किसान परेशान हैं, सरकार चारागाह की भूमि से कब्जा नही हटा पा रही है, पूर्व सरकार की गौठान योजना में जो बुनियादी ढांचा बना है उसे सहेज नही पा रही है, गाय के नाम पर केवल राजनीति हो रही है, जितेन्द्र सिंह ने कहा कि विधायक कुंवर निषाद के प्रश्न पर मंत्री राम विचार नेताम ने आंकड़ा बताते हुए कहा है कि घुमंतू पशुओं से फसल को कोई नुकसान नहीं होता ए पशु हवा पीकर रहते हैं या सड़क में घास मिलती है मंत्री जाने लेकिन किसान तबाह है यह हम जानते हैं।

डीएसपी (मुख्यालय) राजेश कुमार झा को गरिमामयी समारोह में दी गई विदाई

■ स्थानांतरण नौकरी का हिस्सा, नई जगह कुछ न कुछ जरूर सीखता : एसपी बेमेतरा त्रिलोक बंसल

बेमेतरा/नवप्रदेश। बेमेतरा पुलिस जिले में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बेमेतरा राजेश कुमार झा का स्थानांतरण राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया। उन्हें पुलिस कार्यालय बेमेतरा के सभा कक्ष में गरिमामयी विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन कर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव, एसडीओपी बेमेतरा भुषण एक्का, डीएसपी शशीकला उईके, रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक सोनल ग्वाला, सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, रीडर-1निरीक्षक कृष्णकांत सिंह ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया एवं उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। साथ ही उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं सुखमय जीवन की कामना की गई। स्थानांतरित उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बेमेतरा श्री राजेश कुमार झा का जिले में लगभग 05 साल का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। अनेक गंभीर मामलों में उनके पर्यवेक्षण से उल्लेखनीय सफलता मिली।

उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) बेमेतरा राजेश कुमार झा ने बेमेतरा जिले में बिताए अपने अनुभव को उपस्थित स्टाफ के साथ साझा किया।

कबीरधाम पुलिस ने 5 वारदातों का किया खुलासा

वृद्ध महिलाओं से चेन स्नेचिंग करने वाला गिरोह गिरफ्तार

कवर्धा / नवप्रदेश।। कबीरधाम जिले में पिछले दो महीनों से वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाकर उनके गले से सोने-चांदी के आभूषण झपटने वाले गिरोह का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। साइबर सेल और थाना पिपरिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तीन मोटरसाइकिल, करीब छह ग्राम सोने के आभूषण, नकदी सहित कुल 3 लाख 41 हजार रुपये की मशरूका बरामद की है। कार्रवाई के साथ ही जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज झपटमारी के पांच मामलों का भी खुलासा हो गया है।

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव (आईपीएस) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा डीएसपी मुख्यालय आशीष शुक्ला एवं एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई थी। टीम में साइबर सेल, थाना पिपरिया, थाना पांडातराई और चौकी पौड़ी के पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। लगातार मिल रही शिकायतों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।

तकनीकी जांच से पुलिस पहुंची आरोपियों तक

वारदातों की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थलों के आसपास के तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और अन्य जानकारियों का विश्लेषण किया। इसके आधार पर नैनदास बंजारे, मनोज जांगड़े और राधेलाल चतुर्वेदी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में तीनों ने झपटमारी की घटनाओं को स्वीकार करते हुए बताया कि वे योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग थाना क्षेत्रों में वारदात करते थे।आरोपियों ने यह भी बताया कि छीने गए सोने के आभूषण नितीश बंशे, खेलन डहरिया और बबला डहरिया को बेच दिए जाते थे। इसके बाद पुलिस ने तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी आरोपियों ने झपटमारी के पांच मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य पहले गांवों में जाकर वृद्ध एवं अकेली महिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखते थे। जब उन्हें महिला अकेली दिखाई देती थी, तब वे मोटरसाइकिल से चेहरे ढंककर पहुंचते और अचानक गले से सोने या चांदी के आभूषण झपटकर तेज रफ्तार से फरार हो जाते थे। वारदात को इस तरह अंजाम दिया जाता था कि पीड़ित महिला आरोपियों की पहचान नहीं कर पाती थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया था।

5 महीने से बंद घोठिया पशु औषधालय इलाज के अभाव में तीन पशुओं की मौत

■ सात गांवों के पशुपालक परेशान, निजी डॉक्टरों के भरोसे इलाज; आंदोलन की चेतावनी

खैरागढ़ / नवप्रदेश। जिले में पशु चिकित्सा विभाग में कर्मचारियो की कमी का असर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ दिखने लगा है। विकासखंड के घोठिया स्थित पशु औषधालय पिछले करीब 5 माह से बंद पड़ा है। औषधालय बंद रहने से इलाके के घोठिया, दामरी, साल्हेभरी, नवागांव, बढ़ईटोला, बल्देवपुर और कलकसा सहित आसपास के बड़े गांवों के पशुपालकों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। इस औषधालय के बंद रहने से सरकारी पशु चिकित्सा सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले सडक़ दुर्घटना में घायल हुए पशुओं की सूचना विभाग को दी गई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका। समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण तीन पशुओं की मौत होने का दावा ग्रामीण कर रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। बढ़ईटोला निवासी उमेश्वर वर्मा ने बताया कि वह अपने बीमार पशु को इलाज के लिए घोठिया पशु औषधालय लेकर पहुंचे, लेकिन वहां ताला लगा मिला। इसी तरह रूसे के किसान कौशल साहू ने भी बताया कि कई बार इलाज के लिए आने पर औषधालय बंद मिला, जिसके बाद उन्हें निजी डॉक्टर से इलाज कराना पड़ा। सरकारी व्यवस्था ठप होने से पशुपालकों को निजी चिकित्सकों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

सूख चुके बोरवेल और हैंडपंपों में फिर से पानी आने लगा

मुंगेली/नवप्रदेश। जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम पंचायत पौनी में वाटर लेबल नीचे चले जाने से हैन्ड पम्प एवं बोर सूख गये थे। अव्यवस्थित रूप से पड़े सूखी खदानों में पानी भारे जाने से सूख चुके बोरवेल और हैंडपंपों में फिर से पानी आने लगा है।

किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने से खेतों में दोबारा हरियाली लौट रही है, वहीं पशुपालकों को भी राहत मिली है। समय पर की गई पहल से जल संकट काफी हद तक दूर हो गया है। क्षेत्र की समस्याओ को निराकरण करने की इच्छा शक्ति हो तो बंजर धरती में हरियाली वापस लाई जा सकती है। ग्राम पंचायत पौनी में वाटर लेबल नीचे चले जाने से बोरवेल एवं हैडपम्प सूख चुके थे। ग्राम में आस-पास जल स्त्रोत न होने के चलते पेय जल से लेकर कृषि कार्य में ग्रामीणो को परेशानी होने लगी थी। ग्रामीणो की समस्या को देख कर सरपंच भारत रत्न मंडेला के प्रयासों पर जल संसाधन विभाग ने दुल्लीपार हाफ डायवर्सन मानपुर शाखा नहर से गांव की सूखी खदान, तालाबों और जलाशयों में पानी छोड़ा। करीब 15 दिनों तक लगातार पानी पहुंचने से वर्षों से सूखी पड़ी खदान पूरी तरह भर गई। इसका सकारात्मक असर आसपास के भू-जल स्तर पर भी देखने को मिला। कई सूख चुके बोरवेल और हैंडपंपों में फिर से पानी आने लगा है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने से खेतों में दोबारा हरियाली लौट रही है, वहीं पशुपालकों को भी राहत मिली है। ग्रामीणों ने बताया कि समय पर यह पहल नहीं होती तो गांव को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता। सरपंच की पहल और जल संसाधन विभाग की तत्परता से गांव में जल संरक्षण को नई दिशा मिली है। पौनी की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन और जनप्रतिनिधि-प्रशासन के बेहतर समन्वय का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है।

जिले में औद्योगिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा

हैवी अर्थ मूविंग संयंत्र के लिए 79.70 एकड़ भूमि की मंजूरी

मुंगेली/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के मानचित्र पर जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के प्रस्तावित हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए ग्राम चंद्रगढ़ी, तहसील पथरिया में 79.70 एकड़ शासकीय भूमि रियायती दर पर आबंटित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ मुंगेली में बड़े औद्योगिक निवेश और आधुनिक विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

यह संयंत्र राज्य का पहला उद्योग होगा, जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। जिले में इस प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम की परियोजना शुरू होने से रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता और सहायक उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीईएमएल संयंत्र जिले में औद्योगिक विकास का आधार बनेगा। कैबिनेट के द्वारा मिली मंजूरी जिले में औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने में ऐतिहासिक कदम है। इससे आधुनिक विनिर्माण का आधार मजबूत होगा तथा स्थानीय युवाओं, उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यह पहल जिले को आधुनिक विनिर्माण और इंजीनियरिंग गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाएगी। विशेष प्रयासों से

परियोजना को मुंगेली तक लाने में मिली सफ्लता - पथरिया एसडीएम रेखा चंद्रा ने बताया कि बीईएमएल की प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रारंभिक स्तर पर रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिलों में भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही थी।

इसी दौरान कंपनी ने जिले में भी उपयुक्त भूमि की उपलब्धता में रुचि व्यक्त की। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा राजस्व विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उपयुक्त शासकीय भूमि की खोज और चिन्हांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की। संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण के बाद 79 एकड़ से अधिक भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। भूमि की उपयोगिता का परीक्षण करने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई।

कलेक्टर ने की त्वरित पहल

पथरिया एसडीएम रेखा चंद्रा ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर बीईएमएल परियोजना के लिए अन्य जिलों में भूमि चिन्हांकन किया जा रहा था, लेकिन कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद्रगढ़ी में उपयुक्त शासकीय भूमि चिन्हित की। सर्वेक्षण, विभागीय अनुमतियों और पहुंच मार्ग की व्यवस्था के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए राशि मंजूर

***15.85 करोड़ की विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति**

रायगढ़/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए जनहित के कार्यों को लगातार स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से 15 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी तथा हजारों ग्रामीणों को बेहतर सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत खरसिया विकासखंड के सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और उन्नयन के लिए 88 लाख 81 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं धरमजयगढ़ विखं के सिविल अस्पताल के निर्माण एवं उन्नयन कार्यों के लिए 5 करोड़ 28 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

दुष्कर्म का फरार आरोपी पटना से गिरफ्तार

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। सरगुजा जिले में 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी तरुण कुमार जायसवाल को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है।

पेज 1 का शेष...

'आंदोलन करना ...

देशभक्त है। उन्होंने युवाओं के आंदोलन और सवाल पूछने की प्रवृत्ति को न सिर्फ जायज ठहराया, बल्कि इसे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक सकारात्मक बदलाव करार दिया।

पीएम और गृहमंत्री ...

चला सकते और वे यह तय नहीं कर सकते कि किस मंत्री को किस दिन सदन में आना चाहिए।

सभापति का हस्तक्षेप: सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि खरगे ने कोई आदेश नहीं बल्कि केवल आसन के जरिए अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा कि वे विपक्ष की इस भावना को गृह मंत्री तक पहुंचाएं, जिस पर रिजिजू ने आश्वासन दिया कि वे यह बात पहुंचा देंगे। हंगामे और नारेबाजी के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे से बढ़ाकर अपराह्न 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

हिरोशिमा बरसी पर श्रद्धांजलि: सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की 81वीं बरसी पर मारे गए लोगों को याद किया और सदन ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। गृह मंत्री के बयान और राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की मांग को लेकर लगातार हंगामा जारी रहा।

संसद ठप होने पर चिंता

बार-बार सदन के बाधित होने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में गलत संदेश जा रहा है कि विपक्ष सदन चलाना नहीं चाहता। संसद न चलने से अंततः जनता का ही नुकसान होता है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री संसद में मौजूद रहते हैं और नियम के मुताबिक जिस मंत्री का विधेयक चर्चा में होता है, वही सदन में उपस्थित रहता है।

वेनेजुएला समेत अमेरिका ...

उनके कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी और वेनेजुएला के अधिकारियों ने एक नए द्विपक्षीय एजेंडे पर बातचीत शुरू की है, जिसमें ड्रग तस्करी से निपटने में सहयोग, वेनेजुएला के फंड की रिहाई, दक्षिण अमेरिकी देश के तेल की बिक्री, माइनिंग एक्सप्लोरेशन और राजनयिक बातचीत को फिर से शुरू करना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जनवरी को शेवरॉन, एक्सॉन, शेल और कोनोकोफिलिप्स जैसी बड़ी तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान, उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी।

23,731 करोड़ की ..

स्तंभ के रूप में स्थापित करेगी। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से देश में सीबीजी उत्पादन को करीब 10 गुना बढ़ाना, निजी निवेश आकर्षित करना और सर्कुलर बायोइकोनॉमी को मजबूत करना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार, स्थिर मूल्य, पूंजी सहायता, पाइपलाइन कनेक्टिविटी, ऋण सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

पाइपलाइन अवसंरचना का विकास

सीबीजी संयंत्रों को गैस पाइपलाइन और सिटी गैस नेटवर्क से जोड़ने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे परिवहन लागत कम होगी और बाजार तक पहुंच आसान होगी।

क्रेडिट गारंटी सुविधा : एमएसएमई आधारित सीबीजी परियोजनाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष क्रेडिट गारंटी तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे महिला उद्यमियों और नए निवेशकों को भी लाभ मिलेगा।

सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड: जिला स्तर पर फीडस्टॉक संसाधनों का आकलन, तकनीक अपनाने, जैविक खाद के मूल्य संवर्धन, क्षमता निर्माण और जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष फंड बनाया जाएगा।

सीमांकन मामलों में लापरवाही पर...

मामलों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सक्षम अधिकारियों के आदेश के बावजूद समय पर सीमांकन न होना नागरिकों के लिए परेशानी का सबब है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए।

अतीक के बेटे की सड़क...

बेकाबू होने से पहले अबान के आखिरी शब्द मुझे बचा लो थे।

परिवार का आपराधिक और त्रासद इतिहास

अतीक अहमद के पांच बेटों में अबान सबसे छोटा था। इससे पहले 2023 में उसका भाई असद भी झांसी में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। वहीं, अप्रैल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी हत्या हो चुकी है।

खाद की कालाबाजारी पर कृषि मंत्री का सख्त रुख, अफसर बख्शे नहीं जाएंगे

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। खाद की कालाबाजारी और अनियमित वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को समय पर और निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। खाद की कालाबाजारी में किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को खाद माफिया पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

नाम/परिवर्तन

मैं कु. हाबी कुमारी गौर (KUM HABI KUMARI GOUR) पिता रूपेश्वर सिंह गौर (RUPESHWAR SINGH GOUR) गाँव / शहर प्लाट नं. 667/19, स्ट्रीट नं. 03, भूरी डबरी धाम, सरस्वती कुंज (वेस्ट) रिसाली, सिविकि सेंटर भिलाई, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ने अपना नाम कु. हाबी कुमारी गौर (KUM HABI KUMARI GOUR) पिता रूपेश्वर सिंह गौर (RUPESHWAR SINGH GOUR) (पुराना नाम) से बदल कर हाबी भोयर (HABI BHOIR) पति श्रवण कुमार भोयर (SHRAWAN KUMAR BHOIR) (नया नाम) रख लिया है।

शपथकर्ती
कु. हाबी कुमारी गौर
पिता रूपेश्वर सिंह गौर
गाँव / शहर प्लाट नं. 667/19,
स्ट्रीट नं. 03, भूरी डबरी धाम,
सरस्वती कुंज (वेस्ट) रिसाली,
सिविक सेंटर भिलाई,
तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार राजनांदगांव (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00051 उसरीबोड़ ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण- आर.डी. 202526420538900005

तहसील राजनांदगांव के प.ह.न. 00051 के अंतर्गत ग्राम उसरीबोड़ के वर्तमान भूमिस्वामी मन्नूलाल पिता/पति झाडूरामपता-सा. देह के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 480/2(0.1540), 678/2(0.0370), 116/2(0.0200), 480/7(0.0530) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता लीलाबाई साहू पिता/पति स्व. मन्नूलाल साहू पता निवासी ग्राम कच्चे तह. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण / अभिलेख दुरुस्ती / खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 14/08/2026 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय नायब तहसीलदार राजनांदगांव पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/ आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06.08.2026 को जारी किया जाता है।

मुहर
नायब तहसीलदार
राजनांदगांव (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र/202606101200032 /अ-06अ/ वर्ष 2025-26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संत लाल निषाद पिता कंशी राम निषाद निवासी ग्राम विनायकपुर तह.व जिला दुर्ग के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पिता भूमि मौजा ग्राम विनायकपुर, प.ह.न. 32, रा.नि.म. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 258 रकबा 0.500 हे. भूमि आवेदक के नाम पर से दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम संतराम पिता बंशी एवं जाति धोबी दर्ज है। जो कि त्रुटिपूर्ण है। आवेदक के पिता का सही व सत्य नाम कंशी एवं जाति केंवट है, जो उक्त भूमि के पंजीकृत रजिस्ट्री पेपर में दर्ज है। उक्त आवेदित भूमि के ऑनलाईन रिकार्ड में हुई त्रुटि को सुधार कर भूमि में दर्ज नाम संतराम पिता बंशी एवं जाति धोबी के स्थान पर संतराम पिता कंशी एवं जाति केंवट राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.08.2026 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 03.08.2026 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

NAME CHANGE

It is informed to the general public, that I Rajesh Kumar Takey S/o Ram Bhau Takey, resident of Q.No.-B/5, Vidhyut Nagar, Durg, Chhattisgarh, have changed my old name Rajesh Kumar Takey S/o Ram Bhau Takey. So in future, I should be recognized by my new name, that is Rajesh Takey S/o Ram Bhau Takey in all government and other documents.

Rajesh Takey
S/o Ram Bhau Takey,
resident of Q.No.-B/5,
Vidhyut Nagar, Durg,
Chhattisgarh Pin 491001

नाम/परिवर्तन

मैं किरण मरकाम (KIRAN MARKAM) (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/ सुपुत्री/पत्नी अक्षय कुमार मरकाम (AKSHAY KUAMR MARKAM) वर्तमान निवासी-बिरनपुर, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) एतद् द्वारा मैं पूर्णतः पुष्टि करती हूँ तथा निम्नानुसार घोषित करती हूँ। मैं बिरनपुर, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) की स्थायी निवासी हूँ। मेरा पुराना नाम किरण मरकाम (KIRAN MARKAM) पति अक्षय कुमार मरकाम (AKSHAY KUAMR MARKAM) है और मैं अपना नाम बदलकर नया नाम किरण (KIRAN) पति अक्षय कुमार मरकाम (AKSHAY KUAMR MARKAM) करवाना चाहती हूं। मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में ऋण की राशि शेष है। मैं नाम बदलकर, यदि कोई, गैर कानूनी काम कार्य करती हूं, तो उसके लिए मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। यह शपथ पत्र अपने परे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर कर रही हूं तथा सक्षम अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।

शपथकर्ती
किरण मरकाम
पति अक्षय कुमार मरकाम
वर्तमान निवासी-बिरनपुर, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय, नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. वपुअ/नेसुचंबो/रापुअका/चंद/राय/साअ/ 60/2026, दिनांक 05/08/2026

कार्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी, रायपुर में Construction of Kitchen Shed for DSP Mess, Construction of Tradesman's Workshop निर्माण कार्य एवं Painting Work of DSP Mess (Officer's Mess Grade-I) अनुरक्षण कार्य वास्ते सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/एजेंसी से 03 लिफाफा पद्धति में कार्य बाबत् मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.	निर्माण कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि	अमानत राशि (ईएमडी)	कार्य पूर्ण करने की तिथि (वर्कआर्डर जारी दिनांक से)
1	Construction of Kitchen Shed for DSP Mess at NSCB State Police Academy	4,45,493/-	01%	04 माह
2	Construction of Tradesman's Workshop at Police Academy Chandkhuri	13,75,950/-	01%	
3	Painting Work of DSP Mess (Officer's Mess Grade-I)	4,83,301/-	01%	

1. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि - 14/08/2026 के 05:00 बजे तक
2. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि - -24/08/2026 के 03:00 बजे तक
3. निविदाएं खोलने की तिथि - 24/08/2026 के 03:30 बजे

निविदाएं प्रपत्र संबंधित निविदाकर्ता द्वारा मुख्य शीर्ष 0055-पुलिस, लघु शीर्ष - 800 अन्य प्राप्तिया ' के अंतर्गत निदेशक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी, रायपुर के नाम से राशि रू. 750/- (प्रति कार्य हेतु पृथक-पृथक) जमा किया जाकर मूल चालान प्रति एवं लेटर हेड में आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर निविदा प्रपत्र व शर्ते प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त निर्माण कार्य की विस्तृत निविदा विज्ञप्ति तथा अन्य जानकारियों कार्यालय दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी,
चंदखुरी, रायपुर (छ.ग.)

जी- 262702597/2

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)
ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना

दिनांक 05.08.2026

निम्नांकित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा 'डी' एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों के लिये आमंत्रित की जाती है।

एन.आई.टी क्र/ निविदा क्र.	कार्य का नाम	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
NIT NO. 173 Tender No. 196843	जिला महासमुंद के उपसंभाग पिथौरा अंतर्गत मुख्य जिला मार्गो एवं ग्रामीण मार्गो में पुल पुलियां का विशेष मरम्मत कार्य ।	दिनांक 25.08.2026 प्रथम आमंत्रण	रु 50.00 लाख
NIT NO. 174 Tender No. 196844	बलौदाबाजार अनुविभाग अंतर्गत बम्हनी से भवानीपुर मार्ग लंबाई 1.50 कि.मी. पुल-पुलियां सहित निर्माण कार्य ।	दिनांक 19.08.2026 द्वितीय आमंत्रण	रू 199.94 लाख
NIT NO. 175 Tender No. 196845	कसडोल अनुविभाग अंतर्गत विभिन्न 04 मार्ग लंबाई 114.60 कि.मी. का डब्ल्यू.एम.एम. रिपयेर कार्य।	दिनांक 14.08.2026 तृतीय आमंत्रण	रू 15.99 लाख
NIT NO. 176 Tender No. 196846	जिला गरियाबंद के उपसंभाग क्र. 2 देवभोग के अंतर्गत विभिन्न मार्गो में डब्ल्यू.एम.एम. पेच (ईमल्शन के साथ) मरम्मत कार्य।		रू 15.00 लाख
NIT NO. 177 Tender No. 196847	मेघा सिंगपुर दुगली (मुख्य जिला मार्ग) के कि.मी. 14/10 में कुसुमखुंटा नाले पर पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।		रू 50.00 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम पर एनेक्जर-3 का शपथ पत्र, बिड केपेसीटी उपलब्धता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा, एवं निविदाकारो द्वारा प्रेषित मूल अभिलेख के लिफाफा में निविदाकार अपना मोबाईल न. एवं इमेल आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रुप से करें।

Credible Chhattisgarh
आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

जी-262702603/8

अधीक्षण अभियंता,
लो.नि.वि.,रायपुर मण्डल क्र. 2 (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर, (जोन क्र. - 5)
ईदगाहभाठा, नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

ईश्तहार

नामंतरण प्र.क्र. 33954 दिनांक 06.08.2026
वार्ड का नाम- 68 - डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 68 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. RPR567G00810 जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती LAXMI DEVI VISHWAKARMA पिता / पति श्री/ श्रीमती LATE. RAVI SUNDER VISHWAKARMA के नाम से दर्ज है जिसको श्री/श्रीमती GAUTAM KUMAR पिता /पति श्री/श्रीमती NANDAN YADAV ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी । जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

" सूचना जारी करे "
(जोन कमिश्नर)
जोन (5)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771.4903223
Email: eocghbzone02@gmail.com

आम-सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सामान्य आवास योजनांतर्गत दोंदेखुर्द जिला-रायपुर में स्थित **भवन क्रमांक सीनियर एल.आई.जी.-274, श्री सुदीप गंगोपाध्याय पिता श्री बासाबेंदरा गंगोपाध्याय** के नाम पर आबंटित है। आबंटी द्वारा उक्त भवन की लीजडीड दिनांक 10.01.2011 पंजीकृत कराने उपरान्त भवन की पूर्ण राशि जमाकर दिनांक 28.01.2011 को आधिपत्य आदेश प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में आबंटी श्री सुदीप गंगोपाध्याय पिता श्री बासाबेंदरा गंगोपाध्याय निवासी म.नं.-273 हाउसिंग बोर्ड कालोनी दोंदेखुर्द रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को श्री रविकांत पाण्डेय पिता श्री सुरेश कुमार पाण्डेय निवासी वार्ड नं.-15 सी.सी.आई. रोड छपोरा यश बिल्डींग सेंटर छपोरा तहसील धरसींवा, जिला-रायपुर (छ.ग.) के नाम से विक्रय करने के लिये इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग की गई है।

अतः उक्त भवन के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति, शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक, अथवा वित्तिय संस्था, को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल प्रक्षेत्र-2, रायपुर

संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर
द्वितीय तल, सेक्टर-27, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
ई-मेलः E-mail:sanskriti.rajbhasha@gmail.com, दूरभाषः0771-2995629

''मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना'' हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित

राज्य की कला एवं संस्कृति परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के विविध लोक कलाओं नृत्य संगीत, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास, कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना' स्थापित किया गया है, जिसके लिए प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित है।

1. प्रोत्साहन के लिए निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रविष्टियां पंजीकृत डाक के माध्यक से आमंत्रित की जाती है।

2. प्रोत्साहन का प्रकार :-

क्रमांक	प्रोत्साहन का प्रकार
1	नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार
2	वाद्ययंत्र वादक
3	शिल्प कलाकार
4	छत्तीसगढ़ पाक कला (छत्तीसगढ़ी व्यंजन)
5	छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला (श्रृंगार)

3. वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध किया जाना अनिवार्य है आवेदन प्रारूप विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है एवं कार्यालय संचालनालय संस्कृति विभाग, नवा रायपुर से भी प्राप्त किया जा सकता हैं।

4. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-

- आवेदन वांछित जानकारियों के क्रमानुसार प्रारूप में होना अनिवार्य है।
- चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य है एवं विधावार, निर्धारण वार्षिक प्रोत्साहन न्यूनतम राशि 12,000/- से अधिकतम राशि 24,000/- मात्र ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा।
- लाभान्वित होने वाले कलाकार जिसकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय राशि रूपये 96,000/- से अधिक न हो।
(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें, तहसीलदार द्वारा जारी विगत वित्तीय वर्ष हेतु जारी आय प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जावेगी)
- चयनित कलाकारों दलों को वित्तीय वर्ष में 1 बार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा आगामी 02 वर्षों के लिए अपात्र होंगे।
- बैंक खाता धारक का नाम, खाता क्रमांक एवं आई.एफ.सी. कोड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति ।
- प्रोत्साहन योजना से संबंधित जानकारी विभागीय वेबसाईट WWW.cgculture.in पर भी देखी जा सकती है।
- प्रविष्टियां/प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31.08.2026 है तथा प्रविष्टियों के लिए लिफाफे में विषय 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026' स्पष्ट अंकित किया जावे।
- समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों के संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

जी-262702581/3

संचालक
संस्कृति एवं राजभाषा

मानगढ़ धाम विवादः केंद्र के इनकार पर गरमाई सियासत और इतिहास का सच

नई दिल्ली/ए.। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक मानगढ़ धाम एक बार फिर बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद के केंद्र में आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस स्थल को 'राष्ट्रीय महत्व का स्मारक' घोषित करने से इनकार किए जाने के बाद आदिवासी समाज और विपक्षी दलों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

'आदिवासियों के बलिदान का अपमान' - विपक्षी दलों का हमला

केंद्र सरकार के इस रुख के बाद विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक और बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने केंद्र के बयान को 1,500 आदिवासियों के ऐतिहासिक बलिदान का अपमान बताया है। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और यह साबित होता है कि आदिवासियों का इतिहास भाजपा के लिए कोई महत्व नहीं रखता। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए रैलियों में तो इन स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब सम्मान देने की बारी आती है तो सौतेला व्यवहार किया जाता है। वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि इस फैसले से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आदिवासी विरोधी चेहरा' बेनकाब हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक मानती है और उनकी पहचान का सम्मान नहीं करती।

केंद्र सरकार का तर्क और संसद में बयान

यह पूरा विवाद हाल ही में संसद में उठे एक सवाल के बाद शुरू हुआ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बनने के लिए निर्धारित पात्रता और मानदंडों को पूरा नहीं करता है। मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां काफी निर्माण कार्य हो चुका है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्मारक के लिए जरूरी पुरातात्विक विशेषताएं, प्रमाणिकता और अखंडता अब सुरक्षित नहीं बची है। इससे पहले मार्च में भी भाजपा सांसद मन्ना लाल रावत के सवाल पर सरकार ने ऐसा ही रुख अपनाया था।

मानगढ़ धाम का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व

बांसवाड़ा जिले में गुजरात सीमा के पास स्थित मानगढ़ धाम का इतिहास बहुत दर्दनाक और गौरवशाली है। आदिवासियों का जलियांवाला बागः 17 नवंबर 1913 को समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफएकत्रित हुए लगभग 1,500 भील आदिवासियों पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें वे शहीद हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से छह साल पहले हुई इस घटना को 'आदिवासियों का जलियांवाला बाग' कहा जाता है।

एएम/एनएस इंडिया स्टील ने भारतीय नौसेना के नए पोत आईएनएस मालवन को दी ताकत

नई दिल्ली/मुंबई। 2026: आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) ने भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वॉटरक्राफ्ट 'आईएनएस मालवन' के निर्माण के लिए आवश्यक 100त्न विशेष स्टील की आपूर्ति की है। इस पोत को 22 जुलाई 2026 को कारवार, कर्नाटक में नौसेना में शामिल किया गया। हज़ीरा, गुजरात में स्थित एएम/एनएस इंडिया की एकीकृत इस्पात निर्माण सुविधा में निर्मित, इस पोत में इस्तेमाल किया गया विशेष स्टील देश के बढ़ते रक्षा निर्माण इकोसिस्टम और समुद्री सुरक्षा का समर्थन करने में उन्नत भारतीय इस्पात निर्माण की भूमिका को उजागर करता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति करके भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एएम/एनएस इंडिया के योगदान को और मजबूत करता है। एएम/एनएस इंडिया के निदेशक और उपाध्यक्ष - बिक्री एवं विपणन, श्री रंजन धर ने कहा, आईएनएस मालवन का नौसेना में शामिल होना यह दर्शाता है कि भारत में उन्नत विनिर्माण किस तरह देश की रक्षा तैयारियों का समर्थन कर रहा है। विशेष नौसेना-ग्रेड स्टील के उत्पादन के लिए सख्त गुणवत्ता मानकों, उन्नत धातुकर्म विशेषज्ञता और हमारे ग्राहकों के साथ घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें गर्व है कि एएम/एनएस इंडिया का स्टील भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के जहाजों में योगदान दे रहा है, साथ ही घरेलू रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन कर रहा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित, आईएनएस मालवन आठ माहे-क्लास एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी में से दूसरा है और भारतीय नौसेना के बेड़े में सेवा में प्रवेश करने वाला अपनी श्रेणी का दूसरा पोत है। 80त्न से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित, यह कार्यक्रम भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' पहलों का समर्थन करता है, साथ ही नौसेना डिजाइन, इंजीनियरिंग, सिस्टम एकीकरण और रक्षा पोत निर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे प्रदर्शनकारी छात्र

■ परीक्षाओं में गड़बड़ी पर प्रदर्शन तेज, बातचीत के लिए सरकार ने बनाई टीम

रांची/नवप्रदेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने गुरुवार को कहा कि वे सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बातचीत के लिए शर्त भी रखी है। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी बातचीत बंद कमरे में नहीं बल्कि मीडिया की मौजूदगी में होनी चाहिए। छात्रों ने कहा है कि उनकी मांगें यदि पूरी नहीं हुईं तो वे 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। बता दें कि छात्र जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली एवं अनियमितताओं को लेकर धरना दे रहे हैं।

10 अगस्त को विधानसभा का करेंगे घेराव

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कुमार ने कहा, 'छात्र 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। कल एसडीओ सहित सरकार के कुछ अधिकारी हम लोगों से मिलने आए और हमने अपनी मांगें उन्हें बता दीं। हमारी मांगें यदि पूरी नहीं हुईं तो 10 अगस्त को घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा की तरफकूच करेंगे।' कुमार ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संपन्न जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

महतो से सोनम वांगचुक ने की फोन पर बात : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने का मुद्दा एक राष्ट्रीय समस्या है और उन्होंने इस गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत का प्रस्ताव दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो से बुधवार को बातचीत की और उनसे पानी पीने की अपील की।

गुरुवार से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र में परीक्षाओं में कथित धांधली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। वहीं, छात्रों ने विधानसभा के घेराव की बात कहते हुए हेमंत सरकार पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारी राधे कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से आंदोलनकारी छात्रों के साथ संपर्क करने की पहल के बाद विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया गया।

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत; अंतरिम जमानत नहीं मिली

नई दिल्ली/ए.। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने उन्हें अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयरटेकर रखने की अनुमति दे दी, जो 24 घंटे उनकी चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रख सकेगा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

।। दावा आपत्ति सूचना ।।

क्र./ 451 / राज.वि. / नामां. / 2026
कुम्हारी, दिनांक 23/07/2026

नगर पालिका परिषद कुम्हारी में अपने स्वयं के भवन/भूमियों को कय-विक्रय/वारिसान / मृत्यु आधार आदि में किया जाकर नगर पालिका अभिलेख में नाम परिवर्तन करने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरणों पर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 150 के तहत् नामांतरण किये जाने पर यदि किसी भी व्यक्ति / संस्था / समुदाय को आपत्ति हो तो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित में नगर पालिका कार्यालय में अपना दावा/आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। भवन / भूमि नामांतरण संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.- 1, हस्तांतरणकर्ता का नाम व पता - श्री तरूण कुमार जैन पिता शांति लाल जैन, वार्ड क्र.-14 कुम्हारी जिला-दुर्ग (छ.ग.), **हस्तांतरिती का नाम व पता-** श्री राजीव सिंह पिता बृहस्पति सिंह वार्ड क्र.-14 कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.),
भवन/भूमि का विवरण - खसरा क्र.-359/424 रकबा - 900 वर्गफीट वार्ड क्र.-14 कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.), **नामांतरण का आधार -** विक्रय अभिलेख के आधार पर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद कुम्हारी

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर, (जोन क्र. - 5)
ईदगाहभाठा, नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczone5@gmail.com

ईश्तहार

नामंतरण प्र.क्र. **34173** दिनांक **06.08.2026**
वार्ड का नाम- **42 - महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड **42** स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. **RPR561C00033** जो की निगम अभिलेख श्री/ श्रीमती **KULESWAR PRASAD** पिता / पति श्री/ श्रीमती **UMEDI YADU** के नाम से दर्ज है जिसको श्री/श्रीमती **REKHA YADU** पिता /पति श्री/श्रीमती **MANOJ KUMAR YADU** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / **OTHERS** / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी । जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

" सूचना जारी करे "
(जोन कमिश्नर)
जोन (5)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पुलिस को दी चुनौती

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आईएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि पुलिस बिना किसी लिखित आदेश या आधिकारिक अधिसूचना के मस्जिद कमेटियों पर माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मस्जिद में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो प्रशासन को मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, न कि मौखिक निर्देशों के आधार पर। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अदालत जाने और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को ईमेल भेजने की बात भी कही।

आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे स्थानीय लोगों के कई फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने मस्जिद कमेटियों को बुलाकर माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा है। जब कमेटियों ने पुलिस से इस मांग का आधार जानने के लिए कोई लिखित आदेश या अधिसूचना मांगी, तो पुलिस ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर, (जोन क्र. - 6)
आई.एस.बी.टी., चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

ईश्तहार

नामंतरण प्र.क्र. **34095** दिनांक **05.08.2026**
वार्ड का नाम- **60 - चंद्रशेखर आजाद वार्ड**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड **60** स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. **RPR652F00015** जो की निगम अभिलेख श्री/ श्रीमती **TAPAN KUMAR SAHA** पिता / पति श्री/ श्रीमती **LATE UPENDRA CHANDRA SAHA** के नाम से दर्ज है जिसको श्री/श्रीमती **PURNIMA SAHU** पिता /पति श्री/श्रीमती **W/O DEEPAK KUMAR SAHU** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / **पंजीकृत विक्रय विलेख** / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी । जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

" सूचना जारी करे "
(जोन कमिश्नर)
जोन (6)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर, (जोन क्र. - 6)
आई.एस.बी.टी., चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

ईश्तहार

नामंतरण प्र.क्र. **34099** दिनांक **05.08.2026**
वार्ड का नाम- **60 - चंद्रशेखर आजाद वार्ड**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड **60** स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. **RPR652G0152A** जो की निगम अभिलेख श्री/ श्रीमती **HASIDUN** पिता / पति श्री/ श्रीमती **JULFIKAR AHMED ANSARI** के नाम से दर्ज है जिसको श्री/श्रीमती **1. MOHAMMED RAFIK KHAN 2. SAEEDA BEGUM** पिता /पति श्री/श्रीमती **1. LATE MOHAMMED UMAR KHAN 2. W/O MOHAMMED RAFIK KHAN** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / **OTHERS** / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी । जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

" सूचना जारी करे "
(जोन कमिश्नर)
जोन (6)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर, (जोन क्र. - 6)
आई.एस.बी.टी., चतुर्थ तल, रावणभाठा, रायपुर
Email ID - rmczone6@gmail.com

ईश्तहार

नामंतरण प्र.क्र. **34096** दिनांक **05.08.2026**
वार्ड का नाम- **60 - चंद्रशेखर आजाद वार्ड**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड **60** स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. **RPR652A00378** जो की निगम अभिलेख श्री/ श्रीमती **BABLA VISHWAKARMA** पिता / पति श्री **SAMARU VISHWAKARMA** के नाम से दर्ज है जिसको श्री/श्रीमती ..... पिता /पति श्री/श्रीमती .... ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / **SHAPATH PATRA, SAHMATI PATRA AND DEATH CERTIFICATE** / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी । जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

" सूचना जारी करे "
(जोन कमिश्नर)
जोन (6)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

देशभर में 'बोलती पब्लिक' अभियान चलाएगी सीजेपी

नई दिल्ली/ए.। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर आंदोलन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए पार्टी के आगामी एजेंडे का ऐलान किया।

कार्यालय, नगर पंचायत भिंभौरी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
E-mail-cmobhinbhouree@gmail.com

क्रमांक/521/ लो.नि.शा./न.प./ 2026 भिंभौरी, दिनांक 06.08.2026

रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन क्लीन सिटी अन्तर्गत नगर के प्रत्येक घरों / संस्थानों / दुकानों से निकलने वाले गीले, सूखे एवं घरेलु अपशिष्ट के डोर-टू-डोर पृथक संग्रहण, स्त्रोत पृथकीकरण एवं वैज्ञानिक पद्धति से प्रसंस्करण तथा योजना के अन्य घटक अनुसार गतिविधियों कार्यों व एम.आर.एफ. (एस.एल.आर.एम. सेंटर), कम्पोस्ट शेड, आर.आर.आर. सेंटर, सी एन डी संग्रहण सेंटर का संचालन का कार्य कराया जाना है।

अतः उपरोक्त कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति तिथि 06.08.2026 से आमंत्रित की जाती है। इच्छुक **नगर सीमा की महिला स्वसहायता समूह के द्वारा** उल्लेखित तिथि 01.09.2026 समय 5:00 बजे तक स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक / बंद लिफाफे में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित की जाती है। रूचि की अभिव्यक्ति निर्धारित प्रारूप में समूह से संबंधित आवश्यक दस्तावेंजों, सदस्यों की जानकारी, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधक में अनुभव तथा अन्य अनुभव संबंधी अभिलेखों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे जमा कर सकते है।

कार्य का विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं आमंत्रित रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र निर्धारत शुल्क राशि रू. 100.00 स्थानीय नगरीय निकाय में जमा कर प्राप्त कर सकते है। रूचि अभिव्यक्ति (EOI) वेबसाईट uad.cg.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा-निर्देश व निर्धारित प्रारूप तथा अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवसों मे लोक निर्माण शाखा से संपर्क स्थापित कर उपभियंता / स्वच्छता निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत भिंभौरी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखाः जांजगीर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) 495668

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) **सहपठित नियम 3** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के **नियम 8** के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है ।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का **किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय बैंक ऑफ बड़ौदा के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा** जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	गारंटर/ऋणी का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति का स्वामी	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / कब्जा के प्रकार	मांग पत्र तिथि को बकाया राशि
1.	ऋणी श्री बीरबल निषाद पुत्र उत्तम निषाद	श्री बीरबल निषाद पुत्र उत्तम निषाद के संपत्ति से संबंधितः आवासीय भूमि/मकान खसरा नं. 732/10, शंकर नगर, पीसी नं. 63, वार्ड नं. 28, महर्षि वाल्मीकि वार्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़ । क्षेत्रफल 1250.00 वर्ग फुट में स्थित भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक । चौहद्दीः उत्तर- मुस्लिम भाई की भूमि, दक्षिण- तिवारी की भूमि, पूर्व- सड़क, पश्चिम- सड़क ।	20/05/2026 / 30/07/2026 / सांकेतिक कब्जा	₹ 39,98,680.15 साथ में उस पर ब्याज
2.	ऋणी पंकज केशरवानी एवं श्रीमती अनिता बाई	श्रीमती अनिता बाई केशरवानी से संबंधित संपत्ति- डायवर्टेड भूमि खसरा नं. 3638/2 क्षेत्रफल 0.01 एकड़, 3641/3 क्षेत्रफल 0.04 एकड़, प.ह.नं. 12, ग्राम- बिर्रा, रा.नि.मं.- बिर्रा एवं तहसील- बाम्हनीडीह, जिला- जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक । चौहद्दीः उत्तर- बालमुकुंद की भूमि, दक्षिण- प्रतिभा केशरवानी की भूमि, पूर्व- सड़क, पश्चिम- अमरनाथ कश्यप की भूमि ।	20/05/2026 / 30/07/2026 / सांकेतिक कब्जा	₹ 23,90,019.00 साथ में उस पर ब्याज

दिनांक : 06.08.2026 स्थान : जांजगीर-चांपा (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी / बैंक ऑफ बड़ौदा

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, **Krishna Khandelwal**, residing at 77, A Market, Sector, Bhilai, District Durg, PIN - 491001, Chhattisgarh, do hereby solemnly declare that my old name was **Krishna Khandelwal**, which I have changed and adopted my new name as **Krishna.** Henceforth, I shall be known and recognized by my new name Krishna in all Government, Semi-Government and other official records and documents.

KRISHNA
77, A Market, Sector,
Bhilai, District Durg,
PIN – 491001, Chhattisgarh

कार्यालय नगर पालिका परिषद बेमेतरा जिला- बेमेतरा (छ.ग.),

क्र./1621/न.पा./ लो.नि.वि./2026-27 बेमेतरा दिनांक 05.08.26

// मैनुअल पद्धति से निविदा सूचना //

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत राक्षग श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	विभागीय वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1	मोहभट्ठा गार्डन में मुर्ति स्थापना कार्य।	9.26 लाख	27-08-2026

टीप :- उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट http://uad.cg.gov.in पर डाउनलोड की जा सकती है एवं शाखा से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है। निविदा आमंत्रण से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन सूचना विभाग के वेबसाईट में प्रसारित की जावेगी, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बेमेतरा

कार्यालय नगरपालिका परिषद गरियाबंद, जिला -गरियाबंद (छ.ग.)
दूरभाष 07706-241349 फैक्स नं 07706-241349 Email-nagarpalikagariaband@gmail.com

क्रमांक/463 / न.पा. / लो.नि.शा./ 2026 गरियाबंद, दिनांक 30/07/26

-// भूमि प्रबंधन की सूचना //-
(छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-च के तहत)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छ.ग. नगर पालिका कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तों नियम 2013 के तहत निम्न खसरों की भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि भूमि स्वामीयों द्वारा खसरा नंबर / रकबा की भूमि को भू-खंडो में बॉटकर अवैध तरीके से कॉलोनी का निर्माण किये जाने से संबंधित तथ्य सामने आया है। इस संबंध में निम्न खसरे की भूमि के प्रबंधन का अधिकार विहित प्रावधानों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्यों ना लिया जाये ? के संबंध में निम्न खसरों के सभी हितबध्द पक्षकारों (क्रेता / विक्रेता) को सूचित किया जाता है कि प्रकाशन तिथि के 07 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सम्पूर्ण अवैध कॉलोनी व खसरे का प्रबंधन का अधिकार विहित प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिकार में ले लिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी भूमि के हितबध्द पक्षकारों (क्रेता / विक्रेता) की होगी।

विवरण निम्नानुसार हैः-

01. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद खान 160/1, 160/2, 160/3
02. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 157
03. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 158/1, 158/2, 158/3, 158/4
04. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 147/1, 147/8, 147/5, 147/3, 147/2, 147/4,
05. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 146/1, 146/2, 146/3
06. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 145/1, 145/2
07. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 142/3, 142/2, 142/1.
08. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 141/1, 141/2, 141/3,
09. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 132/1, 132/4.
10. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 135/1, 135/4, 135/2, 135/30,
11. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 134/1, 134/2
12. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5,
13. तहसील गरियाबंद प.ह.नं. 10 ग्राम गरियाबंद ख.नं. 90/3

उपरोक्तानुसार यह सूचना दी जाती है कि जनहित में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त भूमि का 'प्रबंधन क्यों ना सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाये ? इस पर सभी हितबध्द पक्षकार (क्रेता/विक्रेता) कार्यालय नगर पालिका परिषद गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) में तर्कसंगत दस्तावेजों सहित दावा/आपत्ति व अपना जवाब 07 दिवस के भीतर (सूचना प्रकाशन की तिथि से) प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में (छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-च के चहत) प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अवैध रूप से विक्रित भूखंड एवं विकसित किये जा रहें अवैध कॉलोनी की समस्त भूमि को जनहित हेतु मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने व विकास कार्य करने के उद्देश्य से प्रबंधन सक्षम अधिकारी द्वारा अधीनस्त लिया जाना माना जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गरियाबंद
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

महुआ ने बदली महिलाओं की जिंदगी, वन धन योजना से मिली आत्मनिर्भरता की नई पहचान

रायपुर/नवप्रदेश। जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों से लघु वनोपज एकत्र करने वाले आदिवासी समुदायों को प्रशिक्षित करना, उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन करना और उन्हें उद्यमी बनाकर स्थायी आजीविका प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलने वाला महुआ अब ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए आय और आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन बन गया है। राज्य शासन की वन धन विकास केंद्र योजना के माध्यम से महिलाओं को महुआ से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और वे सफल उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

'राजनांदगांव जिले के कोरिनभाठा वन धन विकास केंद्र की सफलता'

राजनांदगांव जिले के कोरिनभाठा वन धन विकास केंद्र की महिलाओं ने इस योजना का पूरा लाभ उठाया है। पहले वे महुआ केवल संग्रह करती थीं, लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद महुआ से लड्डू, कुकीज़, एनर्जी बार, स्क्वैश और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं। आधुनिक प्रसंस्करण और आकर्षक पैकेजिंग के कारण इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग बन रही है।

'प्रशिक्षण और कौशल विकास'

वन धन विकास केंद्र में महिलाओं को केवल उत्पाद बनाना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि गुणवत्ता, स्वच्छ उत्पादन, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण और विपणन की भी जानकारी दी जाती है। इससे वे बाजार की जरूरत के अनुसार बेहतर उत्पाद तैयार कर पा रही हैं और उन्हें उचित मूल्य भी मिल रहा है।

'आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम'

कोरिनभाठा की महिलाओं की यह सफलता दिखाती है कि सही प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और विपणन सहयोग मिलने पर वन संपदा को रोजगार और समृद्धि का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। वन धन विकास केंद्र योजना आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है।

महुआ के मूल्यवर्धन से बढ़ा रोजगार

महुआ के मूल्यवर्धन से उसकी उपयोगिता और बाजार मूल्य दोनों बढ़े हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। महुआ के फूलों और बीजों के मूल्यवर्धन से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की आय कई गुना बढ़ गई है। अब केवल कच्चे महुआ को बेचने के बजाय उससे लड्डू, कुकीज, जैम, और एनर्जी बार जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर नए रोजगार और स्थायी आजीविका के साधन विकसित हुए हैं।

'छत्तीसगढ़ हर्बल्स के माध्यम से बाजार उपलब्धता'

इन उत्पादों को 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के माध्यम से व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे वन आधारित उत्पादों को नई पहचान मिल रही है और ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद संघ की एक अनूठी पहल है। इसके तहत वनों से मिलने वाले प्राकृतिक और शुद्ध उत्पादों जैसे वन शहद, एलोवेरा जेल, हर्बल जूस, महुआ उत्पाद, आयुर्वेदिक चूर्ण और तेलों को महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार कर बेचा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों और स्थानीय लोगों को आजीविका देना है।

न्यूज गैलरी

'आरुग सम्मान समारोह' का पोस्टर रायपुर प्रेस क्लब में विमोचित

रायपुर/नवप्रदेश। लोककला और पंडवानी परंपरा को समर्पित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति में आयोजित होने वाले 'आरुग सम्मान समारोह' के पोस्टर का विमोचन बुधवार को रायपुर प्रेस क्लब में किया गया। यह सम्मान समारोह 7 अगस्त को शहीद स्मारक, रायपुर में आयोजित होगा। कार्यक्रम का आयोजन अलीम बंसी, तीजन बाई के परिवारजनों द्वारा किया जा रहा है। समारोह में लोककला, संस्कृति और पंडवानी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले कलाकारों का सम्मान किया जाएगा तथा स्वर्गीय तीजन बाई के कला-साधना से जुड़े अविस्मरणीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। पोस्टर विमोचन के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी , कोषाध्यक्ष दिनेश यदु सहित आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने प्रदेशवासियों एवं कला प्रेमियों से बड़ी संख्या में समारोह में शामिल होकर स्वर्गीय तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने की अपील की।

रायपुर में मारपीट, चोरी और धमकी के कई मामले दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी रायपुर में मंगलवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी और घर में सेंधमारी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति जैकी जगत और उसके साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने पूर्व में दर्ज रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाते हुए गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर घायल कर दिया। इसी थाना क्षेत्र के काशीराम नगर में घरेलू विवाद को लेकर दो व्यक्तियों पर डंडे और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी स्थित संतोषी मंदिर के पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर युवक से मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आजाद चौक थाना क्षेत्र में रवि भवन के पास खड़ी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वहीं आमानाका थाना क्षेत्र के अरिहंत नगर, सरोना में सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने-चांदी के जेवर, 20 हजार रुपये नकद और सीसीटीवी कैमरा चोरी कर लिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोधीपारा हार्ट बाजार में एक युवक ने आरोप लगाया कि उसे गलत वीडियो दिखाने की बात को लेकर विवाद कर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के रायपुरा स्थित महादेव घाट के पास दो व्यापारियों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया।

हसदेव बराज के कार्यों के लिए 3.83 करोड़ स्वीकृत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोरबा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत हसदेव बरॉज गेट दर्री के सभी गेट स्टाप लॉग एवं संबंधित रेग्यूलेटर गेटों तथा उनके हाइस्टींग एरेंजमेंट के मरम्मत एवं पेटिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 83 लाख 21 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के अंतर्गत कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ की दो बेटियां भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में शामिल

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के खेल जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश की दो होनहार हॉकी खिलाड़ियों गीता यादव और मधु सिदार का चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी अब चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक आयोजित होने वाले जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इतिहास बिलासपुर स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रहीं गीता यादव और मधु सिदार के चयन पर प्रदेशभर में खुशी का माहौल है। उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने दोनों खिलाड़ियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उन्हें भारतीय टीम में चयन के लिए बधाई दी। उन्होंने जूनियर एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों की तैयारियों की जानकारी भी ली। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार और संचालक तनुजा सलाम ने भी दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में चयनित दोनों खिलाड़ी प्रदेश की पहली आवासीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

निक्षय मित्र बनकर जशपुर के निरंजन ने जगाई उम्मीद

19 विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित 60 टीबी मरीजों को गोद लेकर दे रहे नया जीवन

रायपुर/नवप्रदेश। टीबी केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह गरीबी, कुपोषण और सामाजिक उपेक्षा से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक ऐसी ही प्रेरणादायक और मानवीय पहल सामने आई है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला डाटा प्रबंधक निरंजन प्रसाद गुप्ता ने 'निक्षय मित्र' बनकर अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के टीबी मरीजों को संबल प्रदान कर एक नई राह दिखाई है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच स्वास्थ्य की अलख

जशपुर के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण टीबी की पहचान और उपचार हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। कई मरीज पोषणयुक्त भोजन के अभाव में दवाइयां बीच में ही छोड़ देते थे। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए निरंजन गुप्ता ने न केवल पोषण किट उपलब्ध कराई, बल्कि घर-घर जाकर मरीजों और उनके परिजनों को टीबी के लक्षणों, नियमित दवा सेवन, और संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक भी किया।

टीबी मुक्त भारत के लिए जन-भागीदारी की अपील

विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी के सफल उपचार के लिए दवा के साथ-साथ पर्याप्त पोषण बेहद जरूरी है। जशपुर की यह पहल साबित करती है कि यदि समाज का हर सक्षम व्यक्ति संवेदनशीलता के साथ आगे आए, तो देश से टीबी के खात्मे के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक नागरिक और संगठन 'निक्षय मित्र' बनकर इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ें।

60 टीबी रोगियों का जिम्मा

निरंजन प्रसाद गुप्ता ने अक्टूबर 2024 से 'निक्षय मित्र' के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए कुल 60 टीबी मरीजों को गोद लिया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों को संबल

इनमें पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के 19 विशेष पिछड़ी जनजाति मरीज भी शामिल हैं।

नियमित पोषण आहार

दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को नियमित रूप से पोषण आहार एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

राज्य स्तरीय सम्मान

उनके इन उल्लेखनीय और समर्पित प्रयासों के लिए उन्हें दिसंबर 2024 में 'राज्य स्तरीय निक्षय मित्र पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

दुर्ध्यान से सद्ज्ञान की ओर बढ़ने का बनाएं लक्ष्य: मुनिश्री संवेगरत्न सागर

रायपुर/नवप्रदेश। विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में सर्वमंगलमय वर्षावास की चातुर्मासिक प्रवचनमाला में परम पूज्य मुनिश्री संवेगरत्न सागर जी म.सा. ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य का ध्यान उसके मन के माध्यम से होता है। यदि मन अशुभ भावों से ग्रसित हो जाए, तो वह दुर्ध्यान और अज्ञान की ओर बढ़ता है, जबकि सद्ज्ञान आत्मा को सुख, शांति और कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य दुर्ध्यान से निकलकर सद्ज्ञान की ओर बढ़ना होना चाहिए। मुनिश्री ने फरमाया कि ज्ञान में भले ही कोई व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका सम्मान और भक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। ग्रंथों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए तथा प्रभु के वचनों का अनुसरण करना चाहिए। आत्मा के कल्याण के लिए केवल दृष्टिकोण और लक्ष्य बदलने की आवश्यकता है। जिस समर्पण भाव से मनुष्य शरीर के लिए कार्य करता है, उसी भावना से आत्मा के लिए भी प्रयास करना चाहिए। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष जसराज लुणीया व महासचिव सुरेश बरड़िया ने जानकारी दी कि सर्व मंगलमय वर्षावास में तप की निरंतर श्रृंखला जारी है। श्री पंच परमेष्ठी श्रेणी तपः वर्तमान में 49 दिवसीय इस तप का दूसरा चरण चल रहा है।

विशेष तपस्याः इस कड़ी में श्रावक संयम बैद और श्राविका पूजा सुराना ने 9-9 उपवास की तपस्या पूर्ण की।

अज्ञान और दुर्ध्यान के दुष्परिणाम

मुनिश्री ने कहा कि अज्ञान ही मनुष्य को दुर्ध्यान में बांधे रखता है और इससे बचने के लिए प्रायश्चित आवश्यक है। सत्य को जान लेने के बाद भी उसे जीवन में अपनाने से जो शक्ति रोकती है, वही अज्ञान ध्यान है। अविनयपूर्ण आचरण करना और गलत विचारों में उलझे रहना भी अज्ञान ध्यान का ही रूप है, जो मनुष्य को दुख और दुर्गति की ओर ले जाता है। ज्ञान व्यक्ति के दर्शन को निर्मल बनाता है और जीवन में श्रेष्ठ चारित्र्य का निर्माण करता है।

सही चिंतन और मैत्री भाव से जीवन को मिलती है नई दिशा

रायपुर/नवप्रदेश। 'आत्म उत्क्रांति आध्यात्मिक चातुर्मास-2026' के अंतर्गत श्री जिनकुशलसूरि जैन दादाबाड़ी में 'अध्यात्मसार' ग्रंथ के 'चिंतन' अध्याय पर प्रवचन देते हुए पूज्य साध्वी मंजुलाश्रीजी महाराज साहिबा ने कहा कि यदि चिंतन और मनन सही दिशा में किया जाए, तो मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। साध्वीश्री ने कहा कि यदि हमारे मन में यह भाव हो कि हमारी अपेक्षाएं पूरी हों या न हों, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों की अपेक्षाएं अवश्य पूरी हों, तो यही सच्चा मैत्री भाव है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर जीवन में मैत्री और करुणा का स्वाभाविक उदय होता है। जब किसी कार्य के प्रति दृढ़ भाव जागृत हो जाता है, तब वह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, सहज रूप से पूर्ण हो जाता है। सफलता का मूल आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन के सकारात्मक भाव होते हैं। प्रवचन के दौरान उन्होंने एक संत और नगरवासियों का प्रेरक प्रसंग सुनाया। संत के पूछने पर नगरवासियों ने नगर के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में एक झाड़ू लगाने वाली महिला का नाम बताया, जो सदैव प्रसन्न रहती थी, मधुर व्यवहार करती थी और नियमित समाधि का अभ्यास करती थी। महिला ने संत के पूछने पर सहज भाव से उत्तर दिया, समाधि के लिए कुछ नहीं करना पड़ता।÷ इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए साध्वीश्री ने कहा कि जहां मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और भीतर पूर्ण शांति का अनुभव होता है, वहीं से समाधि का आरंभ होता है।

कम्युनिटी बेस्ड सर्विलांस: अब आम नागरिक भी IHIP पोर्टल के जरिए दे सकेंगे संदिग्ध बीमारियों की सूचना

रायपुर/नवप्रदेश। किसी गांव, मोहल्ले या बस्ती में यदि अचानक एक जैसी बीमारी के दो या अधिक मामले सामने आने लगें, तो यह किसी संभावित रोग प्रकोप का संकेत हो सकता है। जनभागीदारी को बढ़ावा देने और बीमारियों की समय रहते पहचान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच के तहत सामुदायिक आधारित रोग निगरानी की सुविधा शुरू की गई है। अब देश का कोई भी नागरिक अपने आसपास फैलने वाली किसी भी असामान्य बीमारी या संभावित रोग प्रकोप की जानकारी सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी संक्रामक बीमारी के फैलाव को रोकने में समय पर जानकारी मिलना सबसे अहम कड़ी है। प्रारंभिक स्तर पर सूचना मिलने से स्वास्थ्य विभाग तुरंत जांच, सैंपल संग्रह, उपचार और नियंत्रण के आवश्यक उपाय शुरू कर सकता है, जिससे बीमारी को महामारी बनने से रोका जा सकता है।

पोर्टल पर कैसे दर्ज करें सूचना?

सामान्य विवरण: सूचना दर्ज करते समय प्रदाता का नाम, मोबाइल नंबर, आयु, लिंग, पता और व्यवसाय जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है।

घटना का विवरण: इसके साथ ही घटना की तिथि, स्थान और बीमारी या स्वास्थ्य समस्या का संक्षिप्त विवरण देना जरूरी है।

प्रमाण: यदि कोई फोटो या अन्य दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उन्हें भी साक्ष्य के रूप में अपलोड किया जा सकता है।

सत्यापन: सभी अनिवार्य विवरण भरने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सत्यापन होते ही सूचना सीधे संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुंच जाती है।

स्वास्थ्य विभाग की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पोर्टल पर केवल सत्य, तथ्यात्मक और जिम्मेदारीपूर्ण जानकारी ही दर्ज करें। अफवाहों, अपुष्ट सूचनाओं या भ्रामक जानकारियों से बचने की सलाह दी गई है ताकि स्वास्थ्य तंत्र वास्तविक और गंभीर मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर सके। आपके द्वारा समय पर दी गई एक सटीक सूचना कई लोगों के जीवन की रक्षा कर सकती है।

अनुकंपा नियुक्ति में सीलिंग हटाने और नई स्थानांतरण नीति लागू करने सीएम को सौंपा ज्ञापन

- तृतीय श्रेणी पदों पर लागू 10% की सीलिंग को तुरंत समाप्त करने की मांग
- 2025 की स्थानांतरण नीति से प्रतिबंध हटाने और नई व्यावहारिक नीति लागू करने का आग्रह

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों से जुड़े दो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से लंबित विषयों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को विस्तृत मांग-पत्र सौंपा है और इस पर त्वरित निर्णय लेने का आग्रह किया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, महासचिव चंद्रशेखर तिवारी, उप संयोजक पवन शर्मा, रोहित तिवारी, संजय सिंह और प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर इन मांगों की पूरी जानकारी दी है।

स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने और नई नीति लागू करने की मांग

फेडरेशन ने वर्ष 2025 की स्थानांतरण नीति में आवश्यक संशोधन कर प्रतिबंध हटाने और नई स्थानांतरण नीति जल्द जारी करने की जोरदार मांग उठाई है। मांग-पत्र में निम्नलिखित प्रावधानों को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर जोर दिया गया है।

पति-पत्नी प्रकरण: पति-पत्नी के मामलों में पारस्परिक स्थानांतरण का स्पष्ट प्रावधान हो।

कर्मचारी संगठन: मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण नियमों में पूर्ववत छूट दी जाए।

विशेष स्वास्थ्य प्राथमिकता: दिव्यांग कर्मचारियों के साथ-साथ कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित शासकीय सेवकों को स्थानांतरण में विशेष छूट और प्राथमिकता मिले। फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि ये दोनों मुद्दे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़े हैं। अनुकंपा नियुक्ति में देरी के कारण शोकाकुल परिवार भयंकर आर्थिक संकट झेल रहे हैं, वहीं स्पष्ट और व्यावहारिक स्थानांतरण नीति के अभाव में कर्मचारी पारिवारिक व मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इन दोनों जनहितैषी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बड़ी मांग

वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के 23 फरवरी 2019 के आदेश के अनुसार, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत की सीमा (सीलिंग) निर्धारित है।

समस्या: इस सीलिंग की वजह से दिवंगत शासकीय सेवकों के उच्च शिक्षित और पात्र आश्रित परिवार वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। इसके विपरीत, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ऐसी कोई सीलिंग लागू नहीं है।

फेडरेशन की मांग: मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी पदों पर भी चतुर्थ श्रेणी की तरह सीलिंग पूरी तरह समाप्त की जाए, जिससे पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय और आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

न्यूज गैलरी

निगम में कार्यशाला, समिति का गठन

रिसाली/नवप्रदेश। महिला उत्पीड़न के शिकायतों के निराकरण करने बनी समिति में अब पुरूष भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच सकते है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बनाएं रखने के लिए आयुक्त मोनिका वर्मा के निर्देश पर रिसाली निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मेरी भागीदारी संस्था के निशा देशमुख व अमोल मालुसरे ने समिति के गठन से लेकर शिकायत कर्ताओं की शिकायतों के संबंध में विस्तार से बताया। निशा देशमुख ने बताया कि समाज में महिला एवं पुरूषों की सहभागिता बराबर है। हर कार्य स्थल पर महिलाएं बराबर अधिकार के साथ कार्य कर रही है। कई बार विषम परिस्थिति निर्मित होने पर महिलाएं शिकायत करने से डरती है। सम्मान में ठेस न पहुंचे इस बात का भय रहता है। उन्होंने उपस्थित महिला एवं पुरूष कर्मचारियों को जानकारी दी कि आंतरिक परिवाद समिति में आवेदन और कार्यवाही दोनो ही गोपनीय रहती है। इसलिए शिकायत के बाद परिचय या फिर नाम सार्वजनिक होने का सवाल ही नहीं रहता। उन्होंने कार्यशाला में यह भी खुलासा किया कि प्रताड़ना संबंधी शिकायत पुरूष भी कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) मे कर सकते है।

बाइक के लिए उतारा मौत के घाट, जेल

भिलाई/नवप्रदेश। जिले के जामुल थाना क्षेत्र में बाइक के लेनदेन को लेकर हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी अरविंद उर्फ लोचन चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त को ग्राम नारधा निवासी भीषम गायकवाड़ पर ओखरा रोड स्थित बरगद के पेड़ के पास धारदार हथियार से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल भीषम को इलाज के लिए मुरमुंदा स्थित मां कर्मा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद जामुल थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में 'संकट में मन की मजबूती' पर व्याख्यान

भिलाई/नवप्रदेश। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी में ब्रह्माकुमारीज के इको केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अभियान के अंतर्गत संकट में मन की मजबूती आत्महत्या नहीं, आत्मशक्ति का चयन विषय पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बी. के. ओंकार चंद शर्मा (माउंट आबू, राजस्थान) ने विद्यार्थियों एवं उपस्थितजनों को मानसिक तनाव, चुनौतियों एवं विपरीत परिस्थितियों का सकारात्मक सोच, आत्मबल एवं आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि संकट क्षणिक होता है, जबकि जीवन अनमोल है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आत्मशक्ति एवं सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अर्चना झा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मबल का विकास अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने की प्रेरणा देते हैं। डीन अकादमिक डॉ. जे. दुर्गा प्रसाद राव ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से सशक्त एवं जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाना भी है।

बैंक खाते किराए पर देने वाले 13 गिरफ्तार : 10 लाख के संदिग्ध ट्रांजेक्शन

■ इन्हीं खातों में जमा हुई साइबर ठगी की रकम

दुर्ग/नवप्रदेश। पुलिस ने 13 ऐसे बैंक खाताधारकों को गिरफ्तार किया है, जिनके खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर-उधर भेजने के लिए किया जा रहा था। पुलिस की जांच में करीब 10 लाख रुपए के संदिग्ध साइबर ट्रांजेक्शन सामने आए हैं। यह कार्रवाई सुपेला थाना, खुर्सीपार थाना और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने की है।

गिरफ्तार किए गए लोग कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड साइबर अपराधियों या उनके एजेंटों को दे देते थे। इसके बाद ठगी से मिली रकम इन्हीं खातों के जरिए अलग-अलग खातों में भेजी जाती थी, ताकि असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाए।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने अपने खाते और बैंक से जुड़े दस्तावेज 2 हजार से 15 हजार रुपए तक के कमीशन के बदले दूसरे लोगों को दिए थे। इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को छिपाने और अलग-अलग जगह ट्रांसफर करने में किया गया। जांच के बाद सुपेला थाना क्षेत्र के बंधन बैंक के 9 खाताधारकों और खुर्सीपार थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक के 4 खाताधारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इस मामले में सुपेला थाना में अपराध दर्ज किया गया है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक से जुड़े अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराध और म्यूल बैंक खातों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान बैंक खातों का तकनीकी विश्लेषण और रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें सामने आया कि कई खातों में साइबर ठगी से जुड़ी रकम का लेनदेन हुआ है।

ये हैं गिरफ्तार 13 आरोपी

डी. श्रीनिवास राव, उम्र 32 वर्ष, निवासी सेक्टर-02, सड़क-15, क्वार्टर नं. 10/ब्, भिलाई। मनीष सिंह मट्टू, उम्र 36 वर्ष, निवासी सेक्टर-02, एवेन्यू-ब्, क्वार्टर नं. 13/, भिलाई। जितेन्द्र साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी करहीडीह, दुर्ग। यश यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी गिरधारी नगर, दुर्ग। मयंक पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी शंकर नगर, दुर्ग। रोशन सारथी, उम्र 24 वर्ष, निवासी बजरंग नगर, दुर्ग। तुषार कसरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी शंकर नगर, दुर्ग। प्रवीण कुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी समोदा, जेवरा सिरसा। प्रवीण कुशवाहा, उम्र 25 वर्ष, निवासी शंकर नगर, वार्ड क्रमांक-10। अजय बंसोड़, उम्र 44 वर्ष, निवासी बीड़ी कॉलोनी, उरला। संगीत साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी शंकर नगर, हरना बांधा, दुर्ग। उभय यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी नेहरू भवन के पीछे, सुपेला। डीलेश मरकाम, निवासी सिकोला बस्ती, दुर्ग।

मुख्यमंत्री साय ने पारस पोर्टल की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की वीडियो कॉन्फ्रेंस से की समीक्षा

दुर्ग/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पारस पोर्टल (प्रोजेक्ट असेसमेंट, रिव्यू एवं एनालिसिस सिस्टम) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। कलेक्टर अभिजीत सिंह एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076 की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता एवं समयबद्ध तरीके से संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य आम नागरिकों को विभागों के चक्कर लगाए बिना उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 721 अधिसूचित सेवाएं प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सेवाओं को अभी तक ऑनलाइन नहीं लाया गया है, उन्हें भी शीघ्र सेवा सेतु से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर तथा अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को नियमित समीक्षा कर ऐसे मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री साय ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने तथा लंबित बकेट क्लेम प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही 30 सितम्बर तक सभी गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने पर जोर दिया।

भिलाई बचाओ पदयात्रा का समापन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

भिलाई/नवप्रदेश। बीएसपी एवं भिलाई टाउनशिप के अस्तित्व को बचाने की मांग को लेकर 'भिलाई बचाओ पदयात्रा' का समापन हुआ। समापन दिवस पर कांग्रेस नेताओं एवं पदयात्रियों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें भिलाई के अस्तित्व, बीएसपी और टाउनशिप की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। भिलाई शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में कांग्रेसजन शामिल हुए। पूर्व विधायक अरुण वोरा एवं आर.एन. वर्मा भी पदयात्रा में सहभागी बने और भिलाई के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष को जनभावनाओं की आवाज बताया। वोरा ने कहा कि भिलाई केवल एक औद्योगिक नगर नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका, पहचान और भविष्य का आधार है। कांग्रेस भिलाई के अस्तित्व और बीएसपी की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी।

महापौर अलका ने किया तीन वार्डों में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन

दुर्ग/नवप्रदेश। नगर पालिक निगम महापौर अलका बाघमार ने आज लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, एमआईसी सदस्य नरेंद्र बंजारे, लीना दिनेश देवांगन, शशि साहू, शेखर चन्द्राकर, पार्षद कुलेश्वर साहू, कमल देवांगन, अनूप सोनी, तुलसी यादव, सहायक अभियंता हरिशंकर साहू, उप अभियंता विनोद मांझी, अपर्णा मिश्रा एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में वार्ड 33, 34 एवं 35 में विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया।

इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने तीनों वार्डों का भ्रमण कर नागरिकों से सीधे संवाद किया तथा उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने।

भूमिपूजन के तहत वार्ड 35 रामदेव वार्ड में 24.38 लाख की से आरसीसी नाली एवं पुलिया निर्माण तथा डोल हरियाणा वाले के घर से माहेश्वरी के घर तक 9.99 लाख की से आरसीसी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य कराया जाएगा।

वहीं वार्ड 34 सरस्वती नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना की एएचपी साइट के समीप 24 लाख से पाइपलाइन विस्तार कार्य, 9 लाख से आरसीसी नाली निर्माण तथा पुलिया निर्माण कार्य किए जाएंगे।

9 लाख से सीसी रोड निर्माण, शिवपारा गवलीपारा, 11 लाख से आरसीसी नाली एवं पुलिया निर्माण तथा 9 लाख से अतिरिक्त नाली निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि निगम का उद्देश्य प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना है। सड़क, नाली, पुलिया और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ विकास नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दीक्षारंभ में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र ने नवप्रवेशी छात्राओं का तिलक लगाकर किया संवाद

दुर्ग/नवप्रदेश। स्कूल शिक्षा मंत्री एवं विधायक गजेन्द्र यादव आज दुर्ग स्थित शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी छात्राओं का तिलक लगाकर एवं पुष्प अर्पित कर आत्मीय स्वागत किये तथा उन्हें महाविद्यालयीन जीवन की नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को महाविद्यालय के वातावरण, शैक्षणिक गतिविधियों एवं अनुशासित छात्र जीवन से परिचित कराना था।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री यादव ने नवप्रवेशी छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता विकसित करने और जीवन के उद्देश्य तय करने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रा अपने भीतर असीम प्रतिभा और संभावनाएं लेकर आती है। आवश्यकता केवल निरंतर अध्ययन, अनुशासन, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की है। शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालय की प्राचार्या, प्राध्यापकों एवं शिक्षण समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर महाविद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्राओं के लिए खेल मैदान सहित अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की मांग रखी गई। इस पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र विस्तृत प्राक्कलन (एस्टीमेट) तैयार करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में सभापति श्याम शर्मा, खालिक रिजवी, दिनेश नालोडे, झरना वर्मा, प्रीती साहू, प्राचार्या रंजना श्रीवास्तव, महाविद्यालय प्राध्यापकगण थे।

बीएसपी ने मासिक उत्पादन का रचा नया कीर्तिमान

भिलाई/नवप्रदेश। इस्पात संयंत्र ने जुलाई 2026 में उत्कृष्ट उत्पादन प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रमुख उत्पादन इकाइयों में अब तक के सर्वश्रेष्ठ जुलाई रिकॉर्ड को उल्लेखनीय अंतर से पीछे छोड़ दिया है। सिंटर प्लांट ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखते हुए कुल सिंटर उत्पादन 7,88,130 टन दर्ज किया, जो जुलाई 2023 के 7,21,848 टन के रिकॉर्ड से अधिक है। यह जुलाई माह के दौरान सभी उत्पादन मानकों में सर्वाधिक परिमाणात्मक वृद्धि रही। वहीं सिंटर प्लांट-3 ने 5,38,741 टन उत्पादन कर जुलाई 2023 में दर्ज अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 5,00,929 टन को पार करते हुए नया मासिक कीर्तिमान स्थापित किया। ब्लास्ट फर्नेस-8 ने 2,60,542 टन हॉट मेटल उत्पादन कर, जुलाई 2023 में दर्ज पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन रिकॉर्ड 2,35,864 टन को पार किया। इसके साथ ही ब्लास्ट फर्नेस-8 ने 2.46 टन प्रति घन मीटर प्रतिदिन की रिकॉर्ड उत्पादकता भी हासिल की, जो जुलाई 2025 के 2.23 टन प्रति घन मीटर प्रतिदिन के पूर्व रिकॉर्ड से बेहतर है। स्टील मेल्टिंग शॉप-3 (एसएमएस-3) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ब्लूम उत्पादन में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। जुलाई 2026 में ब्लूम उत्पादन 1,29,050 टन दर्ज किया गया, जो जुलाई 2023 के 1,07,126 टन के रिकॉर्ड से अधिक है। वहीं कास्ट स्टील उत्पादन 3,38,496 टन दर्ज किया गया। कुल हॉट मेटल उत्पादन 5,44,049 टन रहा, जिसने जुलाई 2023 के 5,09,691 टन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वहीं कुल क्रूड स्टील उत्पादन 5,17,656 टन दर्ज किया गया। इसी प्रकार, कुल सेलेबल स्टील उत्पादन 483949 टन रहा। 4,55,247 टन के पूर्व रिकॉर्ड को पार करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

साइबर सेल और संजय रूंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर

■ विद्यार्थियों के लिए डिजिटल युग की चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने का अवसर : संजय

भिलाई/नवप्रदेश। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने और युवाओं में साइबर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइबर सेल भिलाई और संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स एसआरजीआई में एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस एमओयू का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को साइबर सुरक्षा से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का लाभ प्रदान करना है। इसके अंतर्गतः विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जैसे की नियमित वर्कशॉप, सेमिनार और वेबिनार का आयोजन करना है। साइबर सेल अधिकारियों और रूंगटा कॉलेज के फैकल्टी के द्वारा साइबर कानून, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल एथिक्स पर लेक्चर दिया जायेगा। साथ ही साइबर खतरों की पहचान, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और सुरक्षित डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर डेमो क्लासेज का आयोजन किया जायेगा।

साइबर सुरक्षा अभियानों, प्रतियोगिताओं और जागरूकता ड्राइव में छात्र एवम छात्राओं की भागीदारी होगी। साइबर सेल अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से रूंगटा कॉलेज के फैकल्टीज को केस स्टडी, रिपोर्ट और शोधः प्रकाशन में सहयोग किया जायेगा। यह ख्ष भिलाई में संपन्न हुआ।

साइबर सेल भिलाई की ओर से विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवम संजय रूंगटा ग्रुप ऑफ़इंस्टीटूशन्स की ओर से संजय रुंगटा, चेयरमैन ने हस्ताक्षर किये।

चेयरमैन संजय रुंगटा ने कहा कि यह समझौता हमारे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल युग की चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने का अवसर है।

साइबर सेल भिलाई के साथ मिलकर हम न केवल साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएँगे, बल्कि जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता की सोच भी विकसित करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह सहयोग हमारे छात्रों को सुरक्षित और आत्मविश्वासी डिजिटल भविष्य की ओर ले जाएगा। इस अवसर पर डायरेक्टर डॉ साकेत रूंगटा भी उपस्थित थे।

नवप्रवेशी का किया स्वागत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के दीक्षारंभ समारोह में शामिल हुए विधायक ललित चंद्राकर

आज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने : ललित

भिलाई/नवप्रदेश। शासकीय नवीन महाविद्यालय रिसाली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अंतर्गत दीक्षारंभ समारोह एवं इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं राज्य ग्रामीण तथा अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण तथा राष्ट्रीय गीत एवं राज्य गीत के साथ हुआ। विधायक ने नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का पुष्प एवं तिलक लगाकर स्वागत किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा विश्व की सबसे समृद्ध परंपराओं में रही है और नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इसकी गौरवशाली पहचान हैं। एनईपी-2020 के माध्यम से देश उसी गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विधायक ने कहा कि सीएम साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि पात्र नियमित छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है, ताकि आर्थिक अभाव किसी भी बेटी की शिक्षा में बाधा न बने।

उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बने। स्टार्टअप, नवाचार और कौशल के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महाविद्यालय परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

इस दौरान मंडल अध्यक्ष अनुपम साहू, मंडल महामंत्री नरेन्द्र निर्मलकर, पुनाराम कलिहारी, जिला मंत्री शैलेन्द्र सेंडे, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष एवं पार्षद विधि यादव, सरिता देवांगन, प्राचार्य डॉ. अनुपमा आस्थामा, सीखा तिवारी आदि उपस्थित थे।

गौ सेवा एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

नंदिनी अहिवारा/नवप्रदेश। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नंदिनी खुन्दनी में गौ सेवा एवं सड़क सुरक्षा को समर्पित एक जनजागरूकता अभियान न्यू आदर्श युवा संगठन एवं समाजसेवी दिनेश चतुर्वेदी के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। अभियान के दौरान सड़कों पर विचरण करने वाली गायों के गले में रेडियम पट्टियां बांधी गई, जिससे रात्रि के समय वाहन चालकों को दूर से ही पशु दिखाई दें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस पहल का उद्देश्य न केवल गौवंश की सुरक्षा करना है, बल्कि आम नागरिकों और वाहन चालकों के जीवन की रक्षा करना भी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा यातायात नियमों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने भी इस जनहितकारी अभियान की सराहना करते हुए भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करने का संकल्प लिया। समाजसेवी दिनेश चतुर्वेदी ने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सुरक्षा और जनसेवा से जुड़े ऐसे अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लें। इस दौरान देवऋषि गिधोड़े, शेषराम पटेल, अश्वन डहरिया, आर्यन भारती, मुकेश मधुकर, सूर्या मधुकर मौजूद थे।

बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की संवेदनशील शुरुआत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल की है। इसी क्रम में उन्होंने अपने निवास कार्यालय में एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख विजय तथा 'कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन' की भारत प्रमुख सुश्री स्मिता रांधे से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने के विषय पर व्यापक चर्चा की गई।

बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता: बैठक में एक्सिस बैंक के सी.एस.आर. फंड के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं देने, कौशल आधारित प्रशिक्षण सिखाने और अंततः उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ। यह पहल बच्चों को केवल संस्थागत संरक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने का बड़ा प्रयास है। मंत्री राजवाड़े ने इस दौरान कहा, अनाथ और निराश्रित बच्चों को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा यह प्रयास है कि बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाला प्रत्येक बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़े।

सभी जिलों में होगा योजना का विस्तार: मंत्री ने जानकारी दी कि लगभग एक वर्ष पूर्व सामुदायिक सहयोग से बाल संरक्षण एवं बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के सामाजिक पुनर्वास के लिए यह सराहनीय पहल शुरू की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के पांच जिलों में इसका सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है, और अब इसे और विस्तार देते हुए राज्य के सभी जिलों में लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। श्रीमती राजवाड़े ने जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट क्षेत्र और औद्योगिक घरानों के सामूहिक सहयोग से बच्चों के समग्र विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को डिजिटल प्रशिक्षण, रोजगार मार्गदर्शन और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

- **महत्वपूर्ण पहल:** छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के पुनर्वास व आत्मनिर्भर भविष्य के लिए राज्य स्तरीय कदम उठाया है।
- **बैठक और सहयोग:** एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख विजय और 'कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन' की भारत प्रमुख सुश्री स्मिता रांधे के साथ निवास कार्यालय में विस्तृत चर्चा हुई।
- **सी.एस.आर. फंड का उपयोग:** एक्सिस बैंक के सी.एस.आर. फंड के जरिए बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **विस्तार योजना:** वर्तमान में प्रदेश के 5 जिलों में सफल क्रियान्वयन के बाद अब इसे राज्य के सभी जिलों में लागू करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।

न्यूज गैलरी

कवर्धा जिले के सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के लिए चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आयोजित

कवर्धा/नवप्रदेश। 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम' के तहत जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण 4 से 7 अगस्त तक जिला पंचायत संसाधन केंद्र, डंगनिया में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जनपद पंचायत कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा और पंडरिया क्षेत्र के सरपंचों को नई योजना के सभी जरूरी प्रावधानों से परिचित कराया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में ग्रामीणों को 125 दिवस का रोजगार देने की कार्ययोजना, ग्राम पंचायतों में कार्यों की पहचान, परिसंपत्तियों का निर्माण, रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था, मजदूरी भुगतान की प्रणाली, पारदर्शिता और 'युक्त धारा पोर्टल' जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सरपंचों का ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना है ताकि योजना का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम, अभिषेक अग्रवाल ने प्रशिक्षण में उपस्थित रहकर सरपंचों को योजना के नवीन प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। ऑनलाइन अटेंडेंसः उन्होंने एनएमएमएस (ह्स्स्) के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने और युक्त धारा पोर्टल से कार्यों की स्वीकृति व समय पर मजदूरी भुगतान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पुरानी महात्मा गांधी नरेगा योजना में कई जनकल्याणकारी संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत जी राम जी योजना' लागू की है, जो जिले में 2 जुलाई 2026 से प्रभावशील हो चुकी है। प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी विनायक गुप्ता, समन्वयक तकनीकी अशोक झारिया और कार्यक्रम अधिकारी लवकेश मरकाम द्वारा योजना के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला पंचायत सदस्यः कबीरधाम जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू सहित सभी सदस्यों का प्रशिक्षण ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा (राज्य स्तर) में आयोजित किया गया, जहाँ आयुक्त द्वारा नए अधिनियम और बदलावों की जानकारी दी गई। कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा और पंडरिया के सभी जनपद सदस्यों का प्रशिक्षण दुर्ग संभाग मुख्यालय में चल रहा है, जिसमें ग्रामीण विकास की रूपरेखा और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

इंटर्न डॉक्टरों की मांगों का कांग्रेस ने किया समर्थन

जगदलपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जावेद खान ने इंटर्न डॉक्टरों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इंटर्न डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड 15,900 रुपये से बढ़ाकर तुरंत 30 हजार रुपये किया जाए। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ आदिवासी अंचलों में इंटर्न डॉक्टर दिन-रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी बड़ी जिम्मेदारियों और वर्तमान महंगाई के अनुरूप सम्मानजनक स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, मौजूदा स्टाइपेंड भी समय पर न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जावेद खान ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहाँ इंटर्न डॉक्टरों को सबसे कम स्टाइपेंड दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य ओडिशा में इंटर्न डॉक्टरों को 41 से 44 हजार रुपये तक स्टाइपेंड मिलता है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह राशि मात्र 15,900 रुपये है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय इंटर्न डॉक्टरों को 12 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलता था, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढ़ाकर 15,900 रुपये किया गया था। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इंटर्न डॉक्टरों की इस हड़ताल से बस्तर संभाग सहित पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से अपील की है कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर इन युवा डॉक्टरों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करे और शीघ्र समाधान निकालकर हड़ताल समाप्त कराए। कांग्रेस का कहना है कि इंटर्न डॉक्टर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ और एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि यह हड़ताल लंबी चली और आम जनता को स्वास्थ्य लाभ मिलने में दिक्कतें आईं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सरकार को तुरंत 30 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड लागू करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

सीबीआई की फोन टैपिंग अवैध करार, रिकॉर्डिंग नष्ट करने के निर्देश

बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने श्री रावतपुरा संस्थान के चेयरमैन और कथावाचक रवि शंकर जी महाराज (रावतपुरा सरकार) को फोन टैपिंग मामले में बड़ी राहत दी है। चीफजस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सीबीआई द्वारा की गई फोन टैपिंग को पूरी तरह गैरकानूनी ठहराते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने टैपिंग से हासिल सभी रिकॉर्डिंग्स को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, अदालत ने सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

फोन टैपिंग अवैध और निजता पर हमला

हाईकोर्ट ने कहा कि फोन टैपिंग किसी व्यक्ति की निजता पर सीधा हमला है और इसके लिए तय कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन होना जरूरी है। कोर्ट ने पाया कि टैपिंग के आदेश में किसी सार्वजनिक आपातस्थिति या जनसुरक्षा का जिक्र नहीं था।

बैकडेट मंजूरी पर आपत्ति

हाईकोर्ट ने सीबीआई के शपथपत्र पर कड़ी आपत्ति जताई कि जब मूल आदेश 28 जून 2025 को जारी हुआ, तो गृह मंत्रालय ने 27 दिन पुरानी तारीख से बैकडेट में मंजूरी कैसे दे दी। कोर्ट ने टैपिंग ऑर्डर, गृह मंत्रालय के पुष्टि आदेश और रिव्यू कमेटी की कार्रवाई को रद्द कर दिया।

मामला क्या था

सीबीआई ने 30 जून 2025 को देश भर के 35 मेडिकल संस्थानों के खिलाफ रिश्वत, फर्जी मरीज और 'घोस्ट फैकल्टी' के जरिए निरीक्षण रिपोर्ट मैनेज करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन को भी आरोपी बनाया गया था।

बायोफैच इंडिया-2026 में छाई छत्तीसगढ़ की गूंज

विष्णुभोग चावल और प्राकृतिक शहद ने बटोरी राष्ट्रीय सराहना

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जैविक उत्पादों ने एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आयोजित देश के सबसे बड़े जैविक उद्योग व्यापार मेले 'बायोफैच इंडिया-2026' में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के महिला स्वसहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा तैयार जैविक उत्पादों ने विशेष पहचान बनाई है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के राष्ट्रीय स्टॉल में जिले के प्रसिद्ध 'अरपा बिहान विष्णुभोग राइस' और 'केवची के जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद' का आकर्षक प्रदर्शन किया गया।

इन उत्पादों ने देश-विदेश से पहुंचे खरीदारों, निर्यातकों और उद्योग विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे राज्य के जैविक उत्पादों के लिए नए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों के द्वार खुले हैं। बिहान योजना के तहत महिलाएं अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े व्यापारिक आयोजनों में भाग लेकर 'लखपति दीदी' अभियान को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। जिला मिशन प्रबंधक दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि जिले में जैविक

विष्णुभोग धान और शहद के साथ-साथ सूरन, कटहल और अन्य जैविक सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अपनी उच्च गुणवत्ता और प्राकृतिक पद्धति के कारण राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है।

इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में राज्य स्तर से राज्य कार्यक्रम प्रबंधक राजन सोनी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अभिषेक जायसवाल और तिपान किसान उत्पादक संगठन के सीईओ जितेन्द्र खैरवार ने भाग लिया तथा जिले के उत्पादों का प्रभावी प्रदर्शन कर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सराहना प्राप्त की। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि राज्य के हर जिले के विशिष्ट कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए ताकि किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की आय में सतत वृद्धि हो सके।

बस्तर के केंद्रीय विद्यालयों में स्थायी भवन व स्मार्ट क्लास की मांग

सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर संभाग के केंद्रीय विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति तथा स्थायी भवनों के निर्माण की पुरजोर मांग उठाई और इस संबंध में मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।

सांसद ने बताया कि जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में संचालित केंद्रीय विद्यालय जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों में स्थायी भवन, पर्याप्त कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और अन्य जरूरी आधारभूत संसाधनों का विस्तार किया जाना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही, अध्यापन कार्य को सुचारू बनाने के लिए शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरने की जरूरत है। महेश कश्यप ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि बस्तर के सभी केंद्रीय विद्यालयों का विशेष निरीक्षण कराया जाए। साथ ही, उनकी आवश्यकताओं का आकलन कर स्थायी भवनों, अतिरिक्त कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय और खेल अधोसंरचना के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी विषयों को बेहद गंभीरता से सुना और छात्रहित में इन मांगों पर सकारात्मक विचार करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए वे केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं को लगातार और प्रभावी ढंग से रख रहे हैं। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

चिरायु योजना: जन्म से असमर्थ 6 वर्षीय रिया को मिला नया जीवन

उत्तर बस्तर कांकेर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी 'चिरायु योजना' ने एक बार फिर एक जरूरतमंद परिवार के जीवन में खुशियां लौटा दी हैं। जिला मुख्यालय कांकेर के संजय नगर निवासी अमित सिंदूर की 6 वर्षीय पुत्री रिया सिंदूर, जो जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ थी, का सफल इलाज इस योजना के माध्यम से संभव हो सका है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होने के कारण माता-पिता निजी अस्पताल में इस महंगे उपचार का खर्च उठाने में असमर्थ थे, लेकिन सरकारी योजना ने बच्ची को नया जीवन दे दिया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. ठाकुर ने जानकारी दी कि चिरायु टीम के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान रिया की स्थिति संज्ञान में आई। इसके बाद उसे विस्तृत जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 'कॉक्लियर इम्प्लांट' की सलाह दी। निजी

अस्पतालों में इस प्रकार के जटिल उपचार पर लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन चिरायु योजना के अंतर्गत 06 जुलाई 2026 को एम्स रायपुर में यह ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क किया गया। ऑपरेशन के बाद से रिया के स्वास्थ्य में तेजी से और उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। अब वह सामान्य रूप से सुनने और बोलने लगी है, तथा एम्स रायपुर में उसकी स्पीच थैरेपी की प्रक्रिया जारी है। अपनी बेटी की इस कायापलट से खुश माता-पिता ने शासन और स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद दिया है।

सफल इलाज: कांकेर की जन्म से सुनने और बोलने में असमर्थ 6 वर्षीय रिया सिंदूर का 'चिरायु योजना' के तहत सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया है।

निःशुल्क ऑपरेशन: निजी अस्पतालों में 10 से 12 लाख रुपए खर्च होने वाले इस महंगे उपचार को 6 जुलाई 2026 को एम्स रायपुर में पूरी तरह निःशुल्क किया गया।

स्वास्थ्य में सुधार: ऑपरेशन के बाद बच्ची अब न केवल सुनने लगी है, बल्कि बोलने भी लगी है और वर्तमान में एम्स रायपुर में उसकी थैरेपी चल रही है।

परिवार की प्रतिक्रिया: गरीब माता-पिता ने महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होने पर छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।

बलौदाबाजार के किसानों ने खेती में किया तकनीक इस्तेमाल

ड्रोन से खरपतवार नाशक का छिड़काव कर 40 हेक्टेयर में बचाया समय और श्रम

बलौदाबाजार/नवप्रदेश। जिले के किसान अब खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल कर आधुनिक कृषि की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड भाटापारा के ग्राम पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसानों ने खेती में एक नया उदाहरण पेश करते हुए करीब 40 हेक्टेयर रकबे में ड्रोन के माध्यम से खरपतवार नाशक का छिड़काव करवाया है।

पारंपरिक विधि की तुलना में अत्यधिक फायदेमंद: ग्राम धौरभठा के किसान आलोक जायसवाल एवं खोलवा के कृषक गुड्डू चांडक ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले 2 से 3 एकड़ में छिड़काव करने के लिए 2 मजदूरों को पूरा दिन लग जाता था। वहीं, ड्रोन की मदद से 40 हेक्टेयर का यह बड़ा काम महज एक दिन में ही पूरा हो गया। इसमें पानी की खपत भी कम हुई और किसानों को पीठ पर भारी टंकी ढोने की शारीरिक परेशानी से भी राहत मिली।

ड्रोन छिड़काव के प्रमुख लाभ: समय की बचत: मैनुअल छिड़काव की तुलना में 80 प्रतिशत समय कम लगा।

समान छिड़काव: ड्रोन ने निर्धारित ऊंचाई से एक समान रूप से खरपतवार नाशक का छिड़काव किया, जिससे दवा की बर्बादी कम हुई और फसल पर इसका असर बेहद बेहतर रहा।

लागत में कमी: मजदूरी और दवा दोनों की बचत हुई तथा खरपतवार नियंत्रण अधिक प्रभावी तरीके से हुआ।

प्रशासनिक सहयोग और भविष्य की योजना: जिला प्रशासन द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 4 ड्रोन इफ्को कंपनी के भी हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था से अब छोटे किसानों को भी बेहद कम दर पर ड्रोन सेवा मिल रही है। फिलहाल भाटापारा क्षेत्र में धान और दलहन की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए यह तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसान इस सफल प्रयोग से बेहद संतुष्ट हैं और आने वाले सीजन में और अधिक रकबे में ड्रोन से छिड़काव करवाने की योजना बना रहे हैं।

-आधुनिक कृषि की पहलः बलौदाबाजार जिले के भाटापारा विकासखंड के किसानों ने खेती में तकनीक का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

-ड्रोन से छिड़कावः ग्राम पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसानों ने करीब 40 हेक्टेयर रकबे में ड्रोन के माध्यम से खरपतवार नाशक का छिड़काव करवाया।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व प्रधान संपादक यशवंत धोटे द्वारा मिनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि.शेड नं.74 सेक्टर-सी, उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर रजबंधा मैदान प्रेस काम्पलेक्स रायपुर से प्रकाशित, समाचार संपादक-संदीप दीवान, RNI NO.CHHHIN/2012/41806 फोन : 0771-3526755, 6262188999